https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'मोदी सरकार की जनोपयोगी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाना है'

वर्ष-13, अंक-12 16-30 जून, 2018 (पाक्षिक) ₹20

उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए एलपीजी कनेक्शन
4,10,30,010

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवास
1,00,00,000

उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब वितरित
30,14,82,231

अविद्युतीकृत गांवों की संख्या
0

मुद्रा योजना के तहत लोन स्वीकृत
12,93,98,583

4 साल राजग सरकार

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभार्थी
31,73,00,000

अक्टूबर, 2017 से सौभाग्य योजना के तहत घरों को बिजली
68,89,956

प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत सड़कों का निर्माण
1.69 लाख किमी
राष्ट्रीय राजमार्ग
1,20,543 किमी

स्वच्छ भारत के तहत किए गए शौचालयों का निर्माण
7,87,39,293

साफ नीयत
सही विकास

'संपर्क फॉर समर्थन' अभियान का शुभारंभ | देश विकास पथ पर सतत् अग्रसर | प्रखर देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में राजग सरकार के पिछले 4 चार वर्षों की उपलब्धियों पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, साथ में अन्य वरिष्ठ भाजपा नेतागण

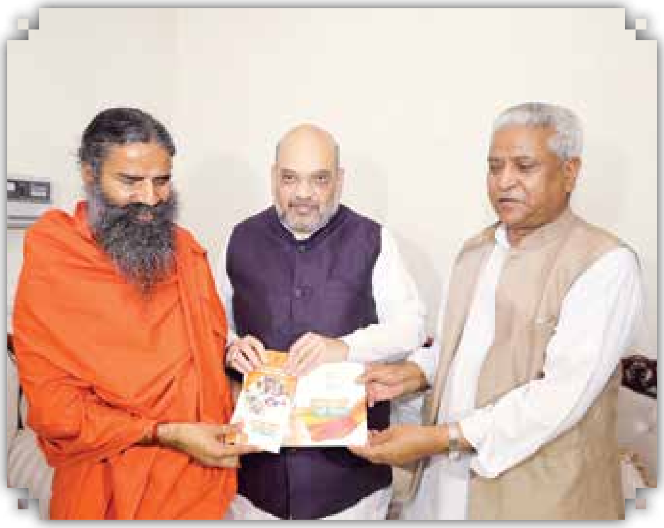

'संपर्क फॉर समर्थन' अभियान के तहत नई दिल्ली में योगगुरु रामदेव को राजग सरकार की उपलब्धियों की पुस्तिकाएं भेंट करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल

नई दिल्ली में देश भर से आए भाजपा सोशल मीडिया के सदस्यों से संवाद करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल और अन्य

'संपर्क फॉर समर्थन' अभियान के तहत मुंबई में प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीमती माधुरी दीक्षित व डॉ. श्रीराम नेने से मिलते श्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस

'संपर्क फॉर समर्थन' अभियान के तहत नई दिल्ली में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी श्री कपिलदेव से मिलते श्री अमित शाह

'संपर्क फॉर समर्थन' अभियान के तहत मुंबई में उद्योगपति श्री रतन टाटा से मिलते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य

कमल संदेश
पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइटः www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **गरीबों का कल्याण हमारी प्राथमिकता : नरेन्द्र मोदी**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एनडीए सरकार के चार वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 26 मई को ओडिशा के कटक में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और कहा कि गरीबों का कल्याण करना ही हमारी प्राथमिकता है, जबकि गरीब एवं विकास विरोधी विपक्ष दुष्प्रचार और नकारात्मक राजनीति में व्यस्त हैं।...

10 **देश की जनता चट्टान की तरह प्रधानमंत्री मोदीजी के साथ खड़ी है: अमित शाह**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 26 मई को भाजपा के केन्द्रीय मुख्यालय में प्रधानमंत्री...

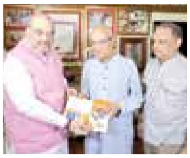

14 **'मोदी सरकार की जनोपयोगी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाना है'**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 4 सफल वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के काम...

18 **ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एवं दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के फेज़-1 का शुभारंभ**

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 मई को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दो नवनिर्मित एक्सप्रेसवे...

19 **मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ परिवारों को 5.75 लाख करोड़ रुपये का मिला ऋण**

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुद्रा...

वैचारिकी
उद्योग 20

श्रद्धांजलि
प्रखर देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी 22

लेख
एनडीए सरकार के चार साल पूरे होने पर मेरी राय 24
देश विकास पथ पर सतत् अग्रसर 29
मोदी सरकार-आर्थिक एवं सामाजिक जनान्दोलन 31
पिछले चार वर्षों में अभूतपूर्व महिला सशक्तिकरण 32

अन्य
2017-18 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.7 फीसदी 17
प्रधानमंत्री का सिंदरी (झारखंड) दौरा 23
महाराष्ट्र के कृषि मंत्री पांडुरंग फुंडकर का निधन 26
प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर यात्रा 27

स्थायी स्तंभ
सोशल मीडिया से 04
व्यंग्य चित्र 04

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

उज्ज्वला योजना बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन ला रही है। लाभार्थियों में अधिकांश महिलाएं हैं जो एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय से संबंधित हैं। दशकों से, उनकी कभी गैस कनेक्शन तक पहुंच नहीं थी ... यह बदल गया है और आज वे बहुत खुश हैं!

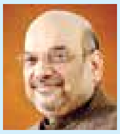

@AmitShah

चुनाव आने वाला है, कांग्रेस लोगों को भ्रमित करने के लिए कई प्रकार के दुष्प्रचारों और झूठे हथकंडों का सहारा फिर लेगी, कांग्रेस पार्टी का काम ही झूठ फैलाकर लोगों को भ्रमित करना है और उन्हें विकास से महरूम रखना है।

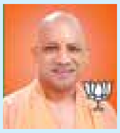

@myogiadityanath

देश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश का विकास आवश्यक है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी विकास कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश पर केन्द्रित करके आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश में 77 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं।

facebook

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि स्वच्छ भारत के लक्ष्य को हासिल करने में राजस्थान ने अग्रणी भूमिका निभाई है। राज्य सरकार ने इस अभियान का सफल संचालन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 79 लाख 30 हजार से अधिक परिवारों को शौचालय सुविधा उपलब्ध कराई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में 3 लाख 25 हजार परिवारों को शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ 2 हजार 248 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण भी करवाया गया है। राज्य सरकार के कुशल नेतृत्व और आमजन की सम्पूर्ण भागीदारी का नतीजा यह रहा कि आज न सिर्फ सभी ग्राम पंचायतें एवं नगर, निकाय बल्कि सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुका है।

— वसुंधरा राजे

आज मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत जबलपुर में आयोजित किसान महासम्मेलन में प्रदेश के 10.80 लाख किसानों के खातों में एक क्लिक से 2245 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। किसान भाइयों ने मांगा नहीं, लेकिन हमने तय किया कि परिश्रम का पूरा हक आपको मिलना चाहिए। इसलिए 1735 रुपए/क्विंटल के समर्थन मूल्य बाद 265 रुपए/क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दे रहा हूं। यानी गेहूं के 2000 रुपए/क्विंटल दे रहा हूं। 27 हजार 350 करोड़ रुपए इस साल विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को दे रहे हैं।

— शिवराज सिंह चौहान

व्यंग्य चित्र

साभार : सोशल मीडिया

साभार : सोशल मीडिया

मोदी सरकार के चार वर्ष

चहुंओर विकास व सुशासन की गूंज

केन्द्र की भाजपानीत राजग सरकार के चार वर्ष होने पर आज जब पूरा देश उत्सव मना रहा है, एक संतोष एवं आशा का भाव आज जन-जन के मन में है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज देश कांग्रेसनीत संप्रग के शासनकाल के भ्रष्टाचार, कुशासन, 'पॉलिसी पैरालिसिस', आर्थिक गिरावट और हर क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों के दौर से उबर चुका है तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदृष्टिपूर्ण एवं मजबूत नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेसनीत संप्रग के उस दौर को कौन भूल सकता है जब हर दिन समाचार पत्र नये-नये घोटालों, भ्रष्टाचार, दहाई आंकड़े को पार करती महंगाई और बिगड़ती अर्थव्यवस्था की खबरों से पटा रहता था। पॉलिसी पैरालिसिस' जैसे शब्द उस समय के वातावरण को इंगित करते थे, जिसमें आपसी मतभेद, विभिन्न मंत्रालयों के विपरीत दिशा में कार्य करने तथा बहुकेन्द्री सत्ता के कारण महत्वपूर्ण विषयों पर भी अनिर्णय की स्थिति बनी रहती थी। नकारात्मकता एवं निराशा से भरे ऐसे वातावरण में लोग भविष्य के प्रति हर उम्मीद छोड़ चुके थे और राजनैतिक व्यवस्था पर से उनका विश्वास हिल गया था। आज जब विश्व समुदाय में भारत अपने उचित स्थान प्राप्त करने का गौरवपूर्ण प्रयत्न कर रहा है, लोग आशा से परिपूर्ण राजनैतिक व्यवस्था को अपना समर्थन दे रहे हैं। आज हर भारतीय का मस्तक गौरव से ऊंचा है और इस विश्वास से ओत-प्रोत है कि देश सुनहरी भविष्य की ओर तेजी से बढ़ चला है।

> अब हर गरीब के पास जन-धन बैंक खाता, महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, घर-घर शौचालय, सामाजिक सुरक्षा एवं स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। इनके अलावा बड़ी संख्या में सुधार कार्यक्रमों से पूरा देश परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है और विकास एवं सुशासन की गूंज हर ओर सुनाई पड़ रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में उनके दूरदृष्टिपूर्ण कार्यक्रमों एवं नीतियों के अन्तर्गत देश अब एक नई दिशा की ओर बढ़ चला है। आज जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है, यह निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करने में निरंतर सफल हो रही है। एक ओर जब महंगाई नियंत्रण में है तथा नोटबंदी एवं जीएसटी जैसे मजबूत निर्णयों से आर्थिक परिदृश्य और अधिक सुदृढ़ हुआ है एवं जिससे औपचारिक अर्थव्यवस्था की पकड़ मजबूत हुई है तथा 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' की दिशा में देश आगे बढ़ा है। कृषि के क्षेत्र में किसानों को अपने उपज की लागत से डेढ़ गुणा अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य से एवं क्रांतिकारी परिवर्तन देश में हो रहा है। कृषि बीमा, बेहतर सिंचाई व्यवस्था, बेहतर बीज एवं खाद की उपलब्धता, सोलर पंप के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा से कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास की नई बयार बह रही है। गरीब एवं वंचितों के प्रति प्रतिबद्धता सरकार की हर नीति एवं कार्यक्रमों में देखी जा सकती है, जिससे लोगों के जीवन में भारी बदलाव हो रहा है। आज जब हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है, सरकार रात-दिन प्रयास कर घर-घर बिजली पहुंचाने में लगी है। हाल में प्रधानमंत्री द्वारा 'आयुष्मान भारत' का शुभारंभ से देश के दस करोड़ परिवारों के स्वास्थ्य रक्षा का कार्यक्रम के अंतर्गत देश की लगभग आधी जनसंख्या को स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का अभिनंदनीय प्रयास हुए हैं। अब हर गरीब के पास जन-धन बैंक खाता, महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, घर-घर शौचालय, सामाजिक सुरक्षा एवं स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। इनके अलावा बड़ी संख्या में सुधार कार्यक्रमों से पूरा देश परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है और विकास एवं सुशासन की गूंज हर ओर सुनाई पड़ रही है।

मोदी सरकार ने अपने चारों वर्षों में राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप इतने व्यापक कार्य किए जो कांग्रेस के लंबे शासनकाल में कभी नहीं हो पाया। आज जब पूरा देश राष्ट्रीय गौरव की अनुभूति कर रहा है, देश को इसकी उपलब्धियों के लिए एक वैश्विक पहचान भी मिल रही है और भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत नेतृत्व का अनुभव हमारी सुरक्षा बलों के बढ़ते आत्मविश्वास में देखा जा सकता है जो आज राष्ट्रविरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं तथा देश की सीमा पार कर 'सर्जिकल स्ट्राईक' कर देश का गौरव बढ़ाया है। अनेक अभूतपूर्व पहलों के कारण देश में चहुंमुखी विकास हो रहा है तथा देश के गरीब, वंचितों, दलित, आदिवासी, महिला, युवा एवं अन्य पिछड़े वर्गों के विकास के लिये बड़े कार्य हो रहे हैं और उनका भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। पिछले चार वर्षों में मां भारती की सेवा में दिन-रात समर्पित एक सरकार देश के लिये गौरवशाली गाथा लिख रही है।■

shivshakti@kamalsandesh.org

गरीबों का कल्याण हमारी प्राथमिकता : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एनडीए सरकार के चार वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 26 मई को ओडिशा के कटक में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और कहा कि गरीबों का कल्याण करना ही हमारी प्राथमिकता है, जबकि गरीब एवं विकास विरोधी विपक्ष दुष्प्रचार और नकारात्मक राजनीति में व्यस्त हैं। उन्होंने कटक की महान धरा को नमन करते हुए देश की सेवा में अपना तन-मन-धन अर्पित कर देने वाले कटक के महान् विभूतियों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने उद्बोधन की शुरुआत की।

श्री मोदी ने कहा कि आज देश के लोगों को यह भरोसा एवं विश्वास है कि केंद्र सरकार कामाख्या, कन्याकुमारी, कश्मीर, कटक से लेकर, बलिया, बीदर, बाड़मेर तक, सबका साथ-सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए, जन-जन के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह वह एनडीए सरकार है जिसके लिए गरीबों का पसीना गंगा-यमुना, नर्मदा-कावेरी-महानदी के जल के समान पवित्र है। यह वह एनडीए सरकार है जिसमें बैठे लोग गरीबी जी कर आये हैं, गरीबी का दुःख सहते हुए आगे बढ़े हैं और इसलिए गरीब की चिंता एवं गरीब कल्याण हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि यह वह एनडीए सरकार है जिसके रहते देश में पहली बार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और मैं आपका प्रधान सेवक, तीनों का ही बचपन एक-एक पैसे की कीमत समझते बीता है, गरीबी का जीवन जीते हुए बीता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 4 सालों में देश के करोड़ों लोगों में यह भरोसा पैदा हुआ है कि हालात बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में एक के बाद एक देश के कई राज्यों के लोगों ने हमारे काम पर जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि जनता के इस आशीर्वाद से साफ है कि हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, ये केवल हमारे दल या किसी नेता की जीत नहीं, बल्कि जनता की, विकास और विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि ये उन माताओं का आशीर्वाद है जिनको उज्ज्वला योजना ने धुएं की जिंदगी से मुक्त किया, ये उन बेटियों की मुस्कान है जिनकी सुरक्षा और पढ़ाई को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की मुहिम ने प्राथमिकता दी, ये उन युवाओं का उत्साह है जिनके सपने मुद्रा योजना और स्किल इंडिया ने पूरे किए और ये उन अन्न-दाताओं-किसानों का आशीर्वाद है, जिनको फसल बीमा, सिंचाई और लागत से डेढ़ गुणा कीमत सुनिश्चित की गई।

श्री मोदी ने कहा कि केंद्र की भाजपा-नीत एनडीए सरकार साफ नीयत के साथ सही विकास कर रही है, उसने दुनिया में देश की साख को और ऊंचा किया है। हम न तो कड़े फैसले लेने से डरते हैं, न बड़े फैसले लेने से। उन्होंने कहा कि जब-जब देश में कंफ्यूजन नहीं, कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, तब ही सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसले लिए जाते हैं, वन रैंक वन पेंशन का दशकों पुराना वादा पूरा किया जाता है, दशकों से अटका हुआ बेनामी संपत्ति कानून लागू होता है दशकों से अटका हुआ बेनामी संपत्ति कानून लागू होता है। दुश्मन की संपत्ति जब्त करने वाला शत्रु संपत्ति कानून लागू होता है और दुश्मन की संपत्ति जब्त करने वाला शत्रु संपत्ति कानून लागू होता है। उन्होंने कहा कि जब नीतियों से जानबूझ कर कंफ्यूजन नहीं फैलाया जाता, जब कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, तब बैंकों से कर्ज लेकर न लौटाने वाली कंपनियों की भी तिजोरी खुलती है, देश को उसका पैसा वापस मिलता है। जब व्यवस्था में कंफ्यूजन नहीं, कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, पारदर्शिता पर जोर दिया जाता है, तब जनधन बैंक खाते, आधार और मोबाइल फोन की शक्ति से 80 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से बचाए जाते हैं, साथ ही राजकोषीय घाटा कम करने का प्रयास सफल होता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्ता के लिए देश को भ्रमित करने वाले, देश से झूठ बोलने वाले लोग न तो कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और न ही देश को टैक्स के जाल से मुक्ति

दिला सकते हैं। उन्होंने कहा कि कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस लड़ाई का कमिटमेंट लेकर हमारी सरकार चल रही है, उसने किस तरह कट्टर दुश्मनों को भी दोस्त बना दिया है, ये भी देश के सवा सौ करोड़ लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में जांच एजेंसियों द्वारा करीब 3 हजार मारे गए छापे में लगभग करीब 53 हजार करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। एजेंसियों द्वारा किए गए 35 हजार से ज्यादा सर्वे में 45 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित आय का पता चला है। उन्होंने कहा कि बेनामी संपत्ति कानून लागू होने के बाद, इतने कम समय में 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कालेधन के खिलाफ सख्त SIT के गठन से लेकर, सख्त कानून बनाने और जांच की वजह से जो हड़कंप मचा है, उसने बहुत से लोगों को 'एक मंच' पर ला खड़ा किया है। 5 हजार करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप में जमानत पर चल रहे लोग हों या अलग-अलग आरापों और घोटालों में घिरे लोग, सब इकट्ठा हो गए हैं। ये सभी खुद को बचाने के लिए, अपने-अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, एक होकर, अस्थिरता पैदा कर, फ़ायदा उठाने की फिराक में हैं।

श्री मोदी ने जनता को याद दिलाते हुए कहा कि ये याद रखना जरूरी है कि Family First के आगे नतमस्तक कांग्रेस के 48 साल में पीढ़ी दर पीढ़ी, कैसे एक परिवार के लिए सत्ता ही सब कुछ रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय लाखों करोड़ के घोटालों-घपलों-भ्रष्टाचार के कारनामों ने देश की साख कहां पहुंचा दी थी, ये देश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि गरीब को सिर्फ गरीबी हटाने के नारे दो, मध्यम वर्ग को सिर्फ टूटी सड़कें, खस्ताहाल स्कूल-अस्पताल, जर्जर यातायात व्यवस्था दो, यही Family First पार्टी के राज की सच्चाई रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने देश को बर्बाद कर के रख दिया। इसी स्थिति की वजह से ऐसे राजनीतिक दलों ने कभी नहीं सोचा कि सबसे पास शौचालय हों, हर घर में बिजली कनेक्शन हो, हर घर में गैस कनेक्शन हो, हर गांव तक सड़क हो, हर बेघर के पास घर हो।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार देश की व्यवस्थाओं को ऐसी अनेक अपूर्णताओं से बाहर निकालकर संपूर्णता की ओर ले जाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज चार वर्ष बाद मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारी सरकार किसी जनपथ से नहीं, जनमत से चल रही है। उन्होंने कहा कि आज देश के संपूर्ण गांवों तक बिजली पहुंच चुकी है। अब सौभाग्य योजना के तहत लगभग 4 करोड़ घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है, जिससे हर घर में बिजली पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि 2014 तक देश में 56 प्रतिशत गांवों तक ही सड़क पहुंच पाई थी। इस साल मार्च तक ये 85 प्रतिशत से ज्यादा हो चुकी है। अगले साल तक देश के ग्रामीण इलाकों में संपूर्ण सड़क कनेक्टिविटी हो जायेगी। उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर 2014 तक देश में लगभग 6 करोड़ शौचालय थे, लेकिन बीते चार साल में साढ़े 7 करोड़ नए शौचालय बनाए गए हैं। इसी तरह जब से देश आज़ाद हुआ, 13 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए, वहीं पिछले 4 साल में हमारी सरकार ने 10 करोड़ से ज्यादा नए LPG कनेक्शन दिए हैं। गैस कनेक्शन का जो दायरा 2014 के पहले सिर्फ 55 प्रतिशत था, अब बढ़कर 81 प्रतिशत से भी ज्यादा हो गया है। उन्होंने कहा कि 1 मई, 2016 को शुरु होने के बाद से अब तक उज्ज्वला योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। ओडिशा की भी 25 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2014 में सिर्फ 53 प्रतिशत भारतीयों के पास ही बैंक अकाउंट थे, अब यह बढ़कर 80 प्रतिशत से ज्यादा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जनधन योजना के तहत खोले गए 32 करोड़ अकाउंट ने गरीब को देश के अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया है। यहां ओडिशा में भी सवा करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते इस योजना के जरिए खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना के माध्यम से पिछले चार साल में 19 करोड़ से ज्यादा गरीबों को, सिर्फ एक रुपए महीने और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर सुरक्षा कवच दिया गया है। इसके अलावा देश में एक करोड़ लोगों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की संपूर्णता देश के गरीब को उसके जीवन की सबसे बड़ी चिंता से बाहर निकालेगी और उन्हें

आज चार वर्ष बाद मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारी सरकार किसी जनपथ से नहीं, जनमत से चल रही है।

आत्मनिर्भर बनायेगी।

श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 50 करोड़ गरीबों को सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से गंभीर बीमारी के लिए हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में भीतर तक समाई व्यवस्था की इस अपूर्णता को समाप्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है और 4 साल का रिकॉर्ड बताता है कि संकल्प से सिद्धि की यह यात्रा नए भारत के लिए नया विश्वास जगाती है। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं को जटिल करने वाले 1400 से ज्यादा पुराने कानून खत्म किए जा चुके हैं। ग्रुप सी और डी की नौकरी में इंटरव्यू लेने की बाध्यता खत्म की जा चुकी है। किसानों पर यूरिया के लिए हफ्तों का इंतजार और लाठी चार्ज का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि 4 साल के कार्यकाल में पासपोर्ट मिलने का समय कम हुआ है, इनकम टैक्स रीफंड मिलने का समय कम हुआ है। कंपनी रजिस्टर कराने का समय भी कम हुआ है। इतना ही नहीं देश में, काला धन का कारोबार करने वाली संदिग्ध कंपनियों की संख्या भी कम हो गई है। 2 लाख 26 हजार संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि देश आज जहां बंदरगाहों पर माल ले आने-जाने में लगने वाला समय घटा हुआ है, वहीं जीएसटी

के बाद लॉजिस्टिक्स सेक्टर का खर्च, ट्रकों का हाईवेज पर लगने वाला समय भी कम हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने महंगाई पर नियंत्रण लगाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 13 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित करने, दशकों से अटकी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने, यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग करने और खेती के आधुनिक तरीकों को बढ़ावा देने की वजह से किसान का खेती पर होने वाला खर्च भी कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर अब 90 रह गई है। 2015 में केंद्र सरकार द्वारा नई रणनीति अपनाने के बाद, ज्यादा से ज्यादा नक्सली मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि हम सिद्धांतों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकारें भले ही बहुमत से बनी हैं, हमने चलाई सर्वमत से हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए Development और Good Governance ही Good Politics है। उन्होंने कहा कि हमने 2022 तक देश के हर गरीब को घर देने का कार्य हाथ में लिया है। किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प लिया है और सरकार की योजनाओं को मध्यम वर्ग की आशाओं-अपेक्षाओं से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी पर सरकार 31 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के तहत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जा रहा है। नए एम्स, नई IIT, नए IIM, बनाए जा रहे हैं। देश के 11 बड़े शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि उजाला योजना के तहत अब तक देश में 30 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब वितरित किए जा चुके हैं जिससे गरीब और विशेष रूप से मध्यम वर्ग को बिजली बिल में सालाना करीब-करीब 16 हजार करोड़ रुपए की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि 3 हजार से ज्यादा जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाईयों की बिक्री, स्टेंट की कीमत में 85 प्रतिशत तक की कमी, Knee इम्प्लांट की कीमत पर नियंत्रण, जैसे अनेक कार्य इस सरकार ने किए हैं जो मध्यम वर्ग को भी बड़ी राहत दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के मध्यम वर्ग से आ रहे युवाओं की Aspiration को समझते हुए हमारी सरकार ने स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की। स्टार्ट अप्स के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनाकर उन्हें भी टैक्स में छूट देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज दोगुनी रफ्तार से सड़कें बन रही हैं, रेल लाइनें बन रही हैं, पोर्ट डवलप हो रहे हैं, गैस पाइपलाइन बिछ रही है, डिजिटल इंडिया के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछ रही है, बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांटों को खोलने का काम चल रहा है, करोड़ों घर बनवाए जा रहे हैं, शौचालय बनवाए जा रहे हैं, अस्पतालों का आधुनिकीकरण हो रहा है, नए अस्पताल बनवाए जा रहे हैं, ऐसी हर योजना, हर परियोजना, अपने साथ विशेषकर मध्यम वर्ग के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आ रही है।

श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नौजवानों और मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं को ध्यान में रख कर Next Generation Infrastructure पर विशेष ध्यान दे रही है। जितना निवेश आज HIGHWAY, RAILWAY, SUBWAY या मेट्रो, AIRWAY, WATERWAY और I-WAY पर किया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया। इस बजट में भी हमने Infrastructure पर खर्च को एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ाया है। भारत में सबसे लंबी सुरंग- लेह और कश्मीर के बीच पहाड़ों को काटकर 14 किलोमीटर लंबी सुरंग अब बन रही है। मुंबई में समंदर पर सबसे लंबा ब्रिज- 22 किलोमीटर का सी-लिंक अब बन रहा है। सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन के लिए अब काम शुरू हुआ है। Delhi Mumbai Industrial Corridor और Western Dedicated Freight Corridor भी जल्द पूरा होने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा भारतमाला के तहत 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके देश में हजारों किलोमीटर लंबी आधुनिक सड़कों का जाल बिछाने का काम शुरू किया गया है। सागरमाला कार्यक्रम के जरिए देश की कोस्टल इकॉनॉमी को मजबूत किया जा रहा है। पुराने बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के साथ ही, नए बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में हमारी

देश के मध्यम वर्ग से आ रहे युवाओं की ASPIRATION को समझते हुए हमारी सरकार ने स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की।

सरकार ने उत्तर पूर्व के विकास के लिए, वहां कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया है। आज उत्तर पूर्व, बाकी देश के साथ रेल नेटवर्क से जुड़ चुका है। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम भी पहली बार देश के रेल नक्शे पर आए हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के लगभग 70 साल में देश में 75 एयरपोर्ट बने जबकि पिछले एक डेढ़ साल में 25 नए एयरपोर्ट जुड़े हैं अर्थात् यानी जितने 70 साल में बने उसके एक तिहाई सिर्फ डेढ़ वर्ष में। आज एसी ट्रेन से जितने लोग सफर करते हैं, उससे अधिक लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में लगभग 1400 आईलैंड के विकास करने का बीड़ा भी उठाया है। पहले चरण में अंडमान-निकोबार में 16 आईलैंड और लक्ष्यद्वीप में 10 आईलैंड के विकास का काम शुरू हुआ है, देश में अगली आर्थिक क्रांति का आधार ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड विदेशी निवेश भारत में हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता के लिए दशकों का इंतजार किया जा रहा था, भारत उनका सदस्य बना है – जैसे MTCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वैसेनार ग्रुप। अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस से लेकर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तक, सभी ने भारत और भारतीयों की प्रतिष्ठा को और आगे

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इन चार वर्षों में हमने सिद्ध किया कि कैसे दृढ़ इच्छाशक्ति और देशवासियों की अथक मेहनत से सब कुछ संभव हैं। हमने साबित किया है कि अगर नीयत साफ है, इरादे नेक हैं, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी देश आपके साथ खड़ा होगा।

श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव के पास ही वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर ना जाना पड़े। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए राजधानी भुवनेश्वर में AIIMS बनाया जा रहा है। इसके अलावे आपके कटक, बेरहामपुर और बुर्ला के मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड किया जा रहा है। ये सिर्फ इलाज के सेंटर नहीं बनेंगे, बल्कि यहां मेडिकल शिक्षा और रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे। यहां नए डॉक्टर और नर्स तैयार करने के लिए हज़ारों नई सीटें जुड़ेंगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल एजुकेशन ही नहीं, बल्कि हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन के भी बड़े संस्थान इस क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं। संबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट और मैनेजमेंट यानि IIM, तो बहरामपुर में Indian Institute of Science Education and Research यानि IISER इस क्षेत्र को नौजवानों को नए अवसर देने वाले हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार ओडिशा के लोगों के विकास के जी जान से जुटी है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार यहां के गरीबों, यहां के किसानों के साथ छल कर कर रही है। इसका सबसे जीवंत उदाहरण है महानदी के पानी को लेकर खड़ा किया गया विवाद। ओडिशा सरकार खुद विधानसभा में ये स्वीकार कर चुकी है कि महानदी का आधे से ज्यादा पानी बंगाल की खाड़ी में व्यर्थ बह जाता है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार द्वारा महानदी जल पर विवाद को सुलझाने के लिए प्रयास किया गया, तो ओडिशा सरकार ने उससे भी हाथ पीछे खींच लिए। खुद नितिन गडकरी जी ने भी नवीन पटनायक जी को चिट्ठी लिखकर कहा कि इस विवाद को समयबद्ध तरीके से सुलझाने के लिए काम करते हैं। एक ट्राइब्यूनल बनाने का भी प्रस्ताव रखा, वो भी ठुकरा दिया। इतने साल के शासन के बावजूद राज्य सरकार ऐसी व्यवस्थाएं ही विकसित नहीं कर सकी कि महानदी का जल यहां के गरीबों, यहां कि किसानों को लाभ पहुंचाए, उनके खेतों को सींच पाए। इतना ही नहीं, महानदी के अलावा ओडिशा में जो पांच नदियां बहती हैं, उनके जल का भी उचित इस्तेमाल ओडिशा की राज्य सरकार नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि आज ओडिशा के लोग जानना चाहते हैं कि 20 साल पहले शुरू हुआ 'लोवर इंदिरा सिंचाई प्रोजेक्ट' क्यों बरसों तक नहीं पूरा हुआ? आखिर क्यों Ret सिंचाई परियोजना और रुकुरा सिंचाई परियोजनाएं लटकी रहीं। क्यों इन सिंचाई परियोजनाओ को लटकाकर इनकी लागत राशि 4 गुना, 5 गुना बढ़ाई गई? क्यों ओडिशा के किसान को उसके हाल पर छोड़ दिया गया? उन्होंने कहा कि ओडिशा के किसान की स्थिति को बदलने के लिए, उसके खेत तक पानी पहुंचाने का बीड़ा अब केंद्र सरकार ने उठाया है। इन 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अलावे 4 और सिंचाई परियोजनाओं को अगले साल तक पूरा करने करने के लक्ष्य पर हमारी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ओडिशा की ये 8 सिंचाई परियोजनाएं, देश की उन 99 सिंचाई परियोजनाओं में शामिल हैं, जो कई दशकों से अटकी हुई थीं। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार 80 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च कर रही है।

श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की भलाई के लिए कई कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को लागत का डेढ़ गुणा MSP मिले ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि किसानों को प्रकृति की मार से बचाने के लिए फसल बीमा योजना चल रही है। माइक्रो इरिगेशन से लेकर सोलर पंप तक की सुविधा किसानों को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसल को आसानी से बेच पाए, इसके लिए देश के 22 हज़ार ग्रामीण हाटों को अपग्रेड किया जा रहा है। ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट यानी GrAM की अवधारणा सामने रखी गई है। इनको E-NAM प्लेटफॉर्म से जुड़ी मंडियों से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा पशु पालन और मछली पालन जैसे काम के लिए भी बढ़ाया गया है। इससे Coastal Region में रहने वाले ओडिशा के भी हमारे किसान और मछुवारे भाइयों को लाभ होने वाला है। इस बजट में गांव और कृषि के लिए कुल 14 लाख करोड़ का प्रावधान किया

जब नीयत साफ हो, तभी सही विकास संभव है और तभी 'सबका साथ, सबका विकास' का संकल्प सिद्ध हो सकता है।

गया है, जो अभूतपूर्व है। ओडिशा जैसे समुद्री किनारे पर बसे इलाकों में Blue Revolution की क्षमता है। कर्नाटक के मछुवारे भाइयों को मछली पकड़ने में सुविधा हो, इसके लिए केंद्र सरकार बड़े ट्रॉलर खरीदने में आर्थिक मदद भी दे रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब नीयत साफ हो, तभी सही विकास संभव है और तभी 'सबका साथ, सबका विकास' का संकल्प सिद्ध हो सकता है, लेकिन जिन्होंने पूरा जीवन अपने परिवार और अपने रिश्तेदार के सपनों को पूरा करने में लगा दिया, वो चार वर्षों की सत्ता विहीनता से ही छटपटाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जब तक राष्ट्र निर्माण के इस महान् यज्ञ में पूरी श्रद्धा से अपनी आहूति डालता रहेगा, तब तक आपका हर प्रयास जनता और हमारे रिश्तों को और मज़बूत ही करेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में, देश के हर कोने में, जनता का हमारे ऊपर विश्वास बढ़ता ही चला गया। उन्होंने कहा कि साफ नीयत और सही विकास के बुलंद नारे के साथ, देश विकास पथ पर इसी ऊर्जा के साथ बढ़ता रहेगा। उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि 2022 में न्यू इंडिया का संकल्प सिद्ध करने के लिए हम सवा सौ करोड़ भारतीय मिलकर कार्य करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें, यही मेरी कामना है। ■

देश की जनता चट्टान की तरह प्रधानमंत्री मोदीजी के साथ खड़ी है: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 26 मई को भाजपा के केन्द्रीय मुख्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया और मोदी सरकार की उपलब्धियों और गरीब-कल्याण की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में चल रही विकास की अविरल गाथा में अटूट विश्वास रखते हुए 2019 में देश की जनता एक बार फिर से अवश्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण जनादेश के साथ सेवा का मौक़ा देगी।

श्री शाह ने कहा कि मैं केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के चार सफल वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देश के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी पूरी कैबिनेट को हार्दिक बधाई देता हूं। इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने सरकार के लोक-कल्याणकारी कार्यों को देश की आम जनता तक पहुंचाया और जनता की भावनाओं, आशाओं व आकांक्षाओं को सरकार तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया है।

उन्होंने कहा कि हमें गर्व की अनुभूति हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को एक भ्रष्टाचार विहीन, पारदर्शी, निर्णायक, लोकाभिमुख और कड़े फैसले लेने वाली सरकार दी है जो सदैव आम-जन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहती है और गांव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े, युवाओं एवं महिलाओं के कल्याण के लिए सतत कार्यरत रहती है।

निराशा और हताशा के माहौल से आशा और उमंगों के भारतवर्ष का सफ़र

श्री शाह ने कहा कि देश 2014 का जनादेश कांग्रेस की यूपीए सरकार के कारण देश में आये हताशा और निराशा के माहौल को ख़त्म कर आशा और उमंगों को परवाज देने वाला जनादेश था। उन्होंने कहा कि संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद संसदीय दल की पहली ही बैठक में श्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, युवा एवं महिलाओं के कल्याण के प्रति समर्पित सरकार होगी और हम देश के गौरव को दुनिया में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आज चार साल बाद जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन संकल्पों को अक्षरशः चरितार्थ कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार लोगों को इस बात की अनुभूति हो रही है कि केंद्र की मोदी सरकार उनकी अपनी सरकार है

और सरकार ने भी अनेक योजनओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति को स्पर्श किया है।

अंतर्द्वंदों से आजादी

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र सरकार को कई प्रकार के अंतर्द्वंदों से भी बाहर निकालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 70 साल के इतिहास में जितनी भी सरकारें आई, वह कई तरह के द्वंद्वों में फंसी रहती थी कि सरकार किसानों का विकास करेगी या उद्योगों को बढ़ावा देगी, गांवों का विकास करेगी या शहरों का विकास करेगी, रिफॉर्म्स पर ध्यान देगी या लोक-कल्याण राज्य की स्थापना के लिए काम करेगी, विदेश नीति को तवज्जो देगी या रक्षा नीति को, सरकार को ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे या फिर जन-प्रतिनिधि। लेकिन मोदी सरकार ने चार सालों में बिना किसी द्वंद्व में फंसे यह सिद्ध कर दिया है कि एक साथ किसानों का भी विकास हो सकता है तो उद्योगों का भी। साथ-साथ गांवों का कायाकल्प भी किया जा सकता है और शहरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जा सकता है, रिफॉर्म्स भी हो सकते हैं और जन-कल्याण के कार्य भी बखूबी अंजाम दिए जा सकते हैं, साथ ही विदेश नीति और रक्षा नीति पर समान रूप से काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज ब्यूरोक्रेट्स और जनता द्वारा चुने हुए जन-प्रतिनिधियों के काम को लेकर भी कोई द्वंद्व नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि योजनायें व नीतियां बनाना और इनकी मॉनिटरिंग जन-प्रतिनिधि करेंगे तो योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन।

देश की राजनीति में सकारात्मक बदलाव

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेन्द्र मोदी के रूप में देश को सर्वाधिक परिश्रम करने वाला प्रधानमंत्री दिया है। उन्होंने कहा कि दिन में 15 से 18 घंटे तक काम करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय एवं विजनरी जन-नेता हैं, वे करोड़ों देशवासियों के लिए अक्षय ऊर्जा के अदम्य स्रोत हैं और हमें इस बात का गौरव है कि वे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से देश की राजनीति में काफी सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में देश में परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का अंत कर पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस एंड डेवलपमेंट के एक नए युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय मीडिया में आये दिन घोटालों के टाइटल बनते थे, आज विकास संबंधी ख़बरें टाइटल बनती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपने हर फैसले के केंद्र में देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े, युवा एवं महिलाओं को रख कर 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत को चरितार्थ करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में चल रही विकास यात्रा में एक के बाद एक, कई राज्य सरकारें जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि आज देश के 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और भाजपा गठबंधन की सरकारें हैं, आज देश के 70% भू-भाग और 65% आबादी पर एनडीए एवं भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा में अहर्निश कार्यरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद से देश में हुए सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, हमारा मत प्रतिशत बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी स्थानीय निकाय के चुनाव में हमें अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, यह मोदी सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर है।

लोक-कल्याणकारी सरकार

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इन चार वर्षों में लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने वाले कई अहम् कार्य किये हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में एक भी ऐसा गांव नहीं हैं, जहां बिजली नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने के बाद अब मोदी सरकार ने 'सौभाग्य योजना' के तहत हर घर में बिजली पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत

आज देश के 70% भू-भाग और 65% आबादी पर एनडीए एवं भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा में अहर्निश कार्यरत है।

देश के एक करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया है, जबकि सरकार ने चार करोड़ अन्य घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसे 2019 के जनादेश से पहले-पहले पूरा कर लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक देश के हर गरीब को छत देने की मुहिम शुरू की है, इस योजना के तहत एक करोड़ घर दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत साढ़े तीन करोड़ से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किये जा चुके हैं जबकि सरकार ने 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की एक पहल पर डेढ़ करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है जो जनता में मोदी सरकार के प्रति विश्वसनीयता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि स्टैंड-अप, स्टार्ट-अप, स्किल इंडिया और मुद्रा योजना के माध्यम से स्वरोजगार की नई पहल की गई है और 'जॉब सीकर' को 'जॉब क्रियेटर' बनाने की राह तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि अकेले मुद्रा योजना के माध्यम से देश के 9 करोड़ से अधिक लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि 7 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कर महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी घोटाले के लाखों करोड़ों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के

काम सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने सरकार के साथ मिलकर देश के 16,850 गांवों में सात जनोपयोगी योजनाओं उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, उजाला, जन-धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा योजना और मिशन इन्द्रधनुष को शत-प्रतिशत पहुंचाने का महती कार्य किया है। उन्होंने कहा कि वर्षों से किसानों की लंबित मांग को पूरा कर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत मूल्य का डेढ़ गुना करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत नमो हेल्थ केयर के माध्यम से देश के 10 करोड़ परिवारों अर्थात् लगभग 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकार ने लिया है जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना से देश के 104 जिलों में लिंगानुपात सुधरा है और अब इसे देश के अन्य जिलों में भी लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मातृ वंदन योजना के जरिये गर्भवती महिलाओं को सहायता पहुंचाई जा रही है, उन्हें 26 सप्ताह के अवकाश का भी लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिशन इंद्रधनुष योजना के जरिये बच्चों और माताओं का टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक से मुक्ति का अभियान भी मोदी सरकार ने शुरू किया है और हज पर महिलाओं को बिना मरहम यात्रा की छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को मिलने वाले पेंशन में भी काफी वृद्धि की गई है।

किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध सरकार

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि बजट को लगभग दोगुना करते हुए किसानों की भलाई के लिए कई इनिशिएटिव लिए हैं, मोदी सरकार कृषि बजट को दुगुना करने वाली पहली सरकार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिये खेत से लेकर खलिहान तक किसानों की फसल को सुरक्षित करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से देश के करोड़ों किसान लगातार लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 9.35% और बागवानी उत्पादों में लगभग 15% की वृद्धि हुई है जो आजादी के बाद सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि सोनिया-मनमोहन की यूपीए सरकार के दौरान जहां कृषि विकास दर ऋणात्मक थी, वहीं मोदी सरकार इसे 4.9% तक ले आई है जो कि एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि दाल उत्पादन में भी 2010-14 की तुलना में लगभग 10% की वृद्धि हुई है और दाल के दामों को भी स्थिर रखने में सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों को दी जाने वाली आवंटित राशि को लगभग दोगुना कर दिया गया है। साथ ही, नीम कोटेड यूरिया के मदद से पेस्टीसाइड के उपयोग और खाद के उपयोग में कमी लाई गई है और खादों के दाम में भी कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए स्वायल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, ई-मंडी इत्यादि योजनाओं के माध्यम से किसानों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने के लिए कार्य किये गए हैं। उन्होंने कहा कि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु 12 करोड़ से अधिक स्वायल हेल्थ कार्ड वितरित किये गए हैं और 275 से अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 50 हजार करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना द्वारा हर खेत तक पानी की पहुंच सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत बांसों को वृक्ष की श्रेणी से निकाल कर घास की श्रेणी में डाला गया है जिससे आदिवासी भाइयों-बहनों की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार लाया जा सकेगा। ई-नाम के माध्यम से किसानों को अपने उत्पादों पर बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत बाजार उपलब्ध कराया गया है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट

श्री शाह ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी मोदी सरकार ने कई कीर्तिमान स्थापित किये हैं। उन्होंने कहा कि भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 5,35,000 करोड़ रुपये की लागत से 53,000 किलोमीटर हाइवे का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेतुभारतम योजना के तहत लगभग 21,000 करोड़ रुपये की लागत से सभी नेशनल हाइवे को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाया जा रहा है जिसे 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे लंबी सुरंग और सबसे लंबा पुल भी मोदी सरकार ने बनाया है। उन्होंने कहा कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन योजना के जरिये भारत ने इस क्षेत्र में भी सफलता के नए आयाम गढ़े हैं। उन्होंने कहा कि 'उड़ान' के माध्यम से जन-साधारण को भी हवाई यात्रा के अवसर उपलब्ध कराये गए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग दो लाख करोड़ रुपये की लागत से 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करने का इनिशिएटिव लिया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है।

आर्थिक विकास की डगर

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। महंगाई दर काबू में है और विदेशी मुद्रा भंडार अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी, दो ऐसे फैसले हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को पारदर्शी अर्थव्यवस्था के रूप में तब्दील करते हुए व्यापक सुधार लाया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की अनुमानित जीडीपी 7.4% है। उन्होंने कहा कि 2013 से 2017

के दौरान देश की जीडीपी लगभग 31% की दर से बढ़ी, जबकि वैश्विक जीडीपी की ग्रोथ महज 4% की दर से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार 294 बिलियन डॉलर से बढ़कर 417 बिलियन डॉलर पहुंच गया है, एफडीआई 35 बिलियन डॉलर से 60 बिलियन डॉलर हो गई है। उन्होंने कहा कि समग्र मुद्रास्फीति और खाद्यान्न मुद्रास्फीति में भारी गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पॉलिसी पैरालिसिस से देश को बाहर निकाल कर विकास के पथ पर अग्रसर किया है। उन्होंने कहा कि डीबीटी से 431 योजनाओं को जोड़ कर लगभग 3.66 लाख करोड़ रुपये का सीधा लाभ लाभार्थियों के एकाउंट में ट्रांसफर किया है, इससे लगभग 83 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी को सर्व सहमति से संघीय ढांचे की व्यवस्था के अनुरूप लागू कर एक राष्ट्र, एक बाजार के कंसेप्ट को सिद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष करदाताओं में लगभग 50% की वृद्धि हुई है, जबकि अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 'भीम' और 'यूपीआई' के जरिये डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिला है और रूपे कार्ड का मार्किट शेयर 36% तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि 'मेक इन इंडिया' अपने लक्ष्य की ओर तेज गति से अग्रसर है और इस क्षेत्र में हम काफी अच्छी प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल चार सालों में मोबाइल बनाने वाली कंपनिया 2 से बढ़कर 120 हो गई है और 1,32,000 करोड़ रुपये के राजस्व से 22 करोड़ मोबाइल सालाना बन रहे हैं।

सशक्त एवं निर्णायक सरकार

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार एक सशक्त, निर्णायक और जनहित एवं राष्ट्रहित में त्वरित फैसले लेने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाने और काले-धन पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाये गए हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी रास्तों से आने वाले काले-धन के रास्तों को बंद किया गया है और कई देशों से काले-धन पर अंकुश लगाने को लेकर समझौते हुए हैं। उन्होंने कहा कि 40 वर्षों से लंबित 'वन रैंक, वन पेंशन' की मांग को पूरा कर मोदी सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और हमारे जवानों के अदम्य शौर्य के बल पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दुनिया में संदेश दिया गया है कि हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि बेनामी संपत्ति क़ानून को कठोरता से लागू किया गया है और आर्थिक गबन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के लिए भी कड़े क़ानून बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाने के लिए और चुनावी राजनीति में से काले-धन के दुष्प्रभाव को निरस्त करने के लिए कैश में लिए जाने वाले चंदे की रकम को दो हजार रुपये तक सीमित करने का साहस भी नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। साथ ही, इलेक्टोरल बांड के जरिये चुनावी चंदे और चुनाव में पारदर्शिता लाने का काम किया गया है।

विश्व मंच पर भारत का सम्मान

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विश्व मंच पर भारत की मान-प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि दाभोस के मंच पर प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन भाषण विश्व मंच पर भारत के बढ़ते साख की बानगी बयान करता है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, फलस्तीन और अफगानिस्तान में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है, यह देश की 125 करोड़ जनता का सम्मान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर योग को पूरे विश्व ने अपनाया है और यूनेस्को ने कुंभ मेले को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि यूएन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिंदी में उद्बोधन देकर पूरे विश्व में राष्ट्रभाषा की महत्ता को प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने कहा कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठित किया गया। साथ ही श्री मोदी के नेतृत्व में भारत कई प्रतिष्ठित एवं अहम् संगठन में भागीदार बना। उन्होंने कहा कि 104 सैटेलाईट को एक साथ अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके अपने आप को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने कहा कि पेरिस जलवायु सम्मेलन में पूरी दुनिया ने भारत के नेतृत्व को स्वीकार किया है जो ऐतिहासिक है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश से अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और गरीबी को हटाकर स्थिरता और विकास के एजेंडे पर काम करना चाहती है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश में विपक्ष द्वारा बार-बार झूठ बोलने, झूठ को जोर से बोलने और झूठ को सार्वजनिक रूप से बोलने की नकारात्मक परिपाटी की राजनीति की शुरुआत की गई है और लगता है कि विपक्ष ने इसी प्रकार की राजनीति को 2019 के लोक सभा चुनाव तक जारी रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी पार्टियां मोदी जी को हटाना चाहती है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश से अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और गरीबी को हटा कर स्थिरता और विकास के एजेंडे पर काम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने लोकतंत्र को ताक पर रख कर अब तक परिवार की ही राजनीति की, आज वे लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। इमरजेंसी में लाखों लोगों को जेल में डालने वाले लोग हमें कह रहे हैं कि आज डर का माहौल है। सभी तरह के मीडिया पर ताले लगाने वाले लोग मीडिया की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, यह कितना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा देश में भय और डर का माहौल बनाया जा रहा है, जबकि पूरे देश की जनता चट्टान की तरह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ खड़ी है। ■

'मोदी सरकार की जनोपयोगी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाना है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 4 सफल वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के काम काज को लेकर जागरूकता पैदा करने और जनता के समर्थन के लिए व्यापक व्यक्तिगत संपर्क अभियान 'संपर्क फॉर समर्थन' प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।

पार्टी अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक, हर पार्टी कार्यकर्ता इस इनिशिएटिव में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह स्वयं मोदी सरकार की उपलब्धियों और शुरू किये गए अन्य लोक-कल्याणकारी एवं जनोपयोगी योजनाओं के विवरण को लेकर कम-से-कम 50 आम लोगों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। श्री शाह संगठन को मजबूत करने और केंद्र की भाजपा-नीत मोदी सरकार के विकास कार्यक्रमों एवं गरीब-कल्याण योजनाओं को समाज के सभी वर्गों तक, जन-जन तक और देश के सभी क्षेत्रों - सुदूर सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध रहे हैं।

इस अभियान में हर पार्टी कार्यकर्ता कम-से-कम 10 लोगों से संपर्क करेंगे और सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यों को जनता के बीच लेकर जायेंगे। इस पहल में कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए 'नमो एप' पर 'संपर्क फॉर समर्थन' नाम से एक विशेष अनुभाग भी उपलब्ध होगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं इनिशिएटिव्स से लाभान्वित हुए लाभार्थियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सीधा संवाद करेंगे। 'संपर्क फॉर समर्थन' पहल की शुरुआत करते हुए उन्होंने इस 28 और 29 मई को क्रमशः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एक लोकप्रिय जन-नेता हैं, वे हमेशा देश की जनता एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में रहते हैं और समय-समय पर विभिन्न विषयों पर 'नमो एप', ऑडियो ब्रिज एवं अन्य माध्यमों उनसे चर्चा करते रहते हैं।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 29 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जनोपयोगी कार्यों के प्रति देश में जागरूकता पैदा करने एवं जनता के समर्थन के लिए व्यापक व्यक्तिगत संपर्क अभियान 'संपर्क फॉर समर्थन' की शुरुआत की।

इस व्यापक जन-संपर्क अभियान 'संपर्क फॉर समर्थन' की शुरुआत करते हुए श्री शाह सबसे पहले पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग के दिल्ली कैंट स्थित आवास गए और केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को उनके साथ साझा किया। उन्होंने श्री सुहाग को केंद्र की भाजपा-नीत एनडीए सरकार की उपलब्धियों पर एक बुकलेट, एक पेन ड्राइव और इससे जुड़े अन्य साहित्य भी भेंट किये। तत्पश्चात् वे प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जी के सैनिक फ़ार्म (नई दिल्ली) स्थित आवास गए और उनके साथ भी केंद्र की भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की एवं इससे जुड़े लिटरेचर भी उन्हें भेंट किये। 'संपर्क फॉर समर्थन' अभियान के तहत श्री शाह मोदी सरकार की उपलब्धियों और शुरू किये गए अन्य लोक-कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कम-से-कम 50 प्रतिष्ठित एवं आम लोगों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने वाले हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक इस व्यापक लोक-संपर्क अभियान की शुरुआत की है जिसमें पार्टी के 4,000 से अधिक चयनित कार्यकर्ता (4000 प्रमुख कार्यकर्ताओं में केन्द्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य एवं वरिष्ठ संगठन पदाधिकारी शामिल हैं।

कार्यक्रम के पश्चात् मीडिया से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक इस व्यापक लोक-संपर्क अभियान की शुरुआत की है जिसमें पार्टी के 4,000 से अधिक चयनित कार्यकर्ता (4000 प्रमुख कार्यकर्ताओं में केन्द्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य एवं वरिष्ठ संगठन पदाधिकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा-नीत सरकार की उपलब्धियों को घर-घर पहुंचायेंगे) देश के एक लाख प्रमुख व्यक्तियों से व्यक्तिगत संपर्क करेंगे जिसमें कला जगत, संविधान विशेषज्ञ, सेना के रिटायर्ड अधिकारी, फिल्म और धर्म जगत

की प्रमुख हस्तियां शामिल होगी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के 50 लाख चयनित कार्यकर्ता मोदी सरकार की जनोपयोगी योजनाओं को देश के हर घर तक पहुंचाएंगे।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा-नीत एनडीए सरकार चार सालों से जिस प्रकार से चली है, इन चार सालों में जिस तरह से सरकार ने जीवन के हर क्षेत्र को ऊपर उठाने का सफल प्रयास किये हैं और इस दिशा में केंद्र सरकार ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, इससे देश की आम जनता को रू-ब-रू कराने के उद्देश्य से इस व्यापक 'संपर्क फॉर समर्थन' अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के ये इनिशिएटिव्स ऐसे हैं, जिसकी राह देश के लोग लंबे समय से देख रहे थे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार के इन चार सालों के दौरान विशेषकर दो क्षेत्रों - ग्रामीण जीवन से असुविधाओं को समाप्त कर उन्हें प्रगति की राह पर आगे बढ़ाने और गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले पांचवें साल में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार का लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देकर किसानों के जीवन में

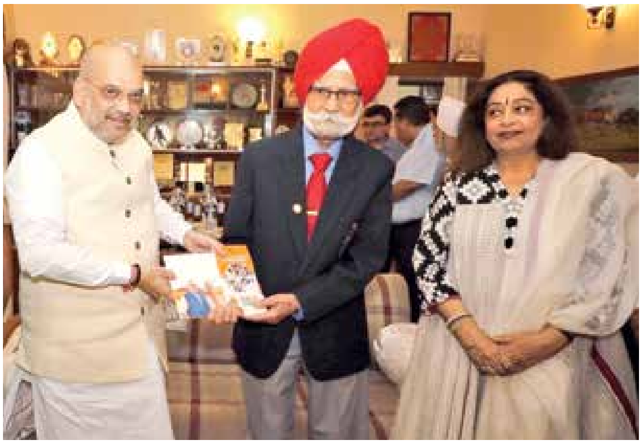

आमूल-चूल परिवर्तन लाने और देश के लगभग 50 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये तक का बीमा देकर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि विगत चार वर्षों में दुनिया में देश के गौरव को आजादी के बाद सबसे ऊंची सतह पर प्रतिष्ठित करने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है।

'सम्पर्क फॉर समर्थन' अभियान के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान श्री कपिल देव एवं उनकी पत्नी, योगगुरू बाबा रामदेव तथा सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री आर. सी. लाहोटी से नई दिल्ली स्थित उनके निवास में मिले; सुप्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीमती माधुरी दीक्षित एवं डॉ. श्रीराम नेने तथा उद्योगपति श्री रतन टाटा से मुंबई स्थित उनके निवास में मिले; शिव सेना प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे से मुंबई स्थित मातोश्री में मिले; शिरोमणि अकाली दल के नेता श्री प्रकाश सिंह बादल एवं श्री सुखवीर सिंह बादल से चंडीगढ़ स्थित उनके निवास में मिले; पूर्व हॉकी खिलाड़ी श्री बलबीर सिंह से, 'फ्लाइंग सिख' श्री मिल्खा सिंह एवं उनकी पत्नी श्रीमती निर्मल मिल्खा सिंह से चंडीगढ़ स्थित उनके निवास पर मिलकर उन्हें मोदी सरकार के 4 साल की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। ■

2017-18 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.7 फीसदी

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में देश की आर्थिक वृद्धि दर पिछली सात तिमाहियों में सर्वाधिक 7.7 प्रतिशत पर पहुंच गई। दरअसल, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में वर्ष 2011-12 के मूल्यों पर जीडीपी वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत आंकी, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 की प्रथम तीन तिमाहियों यथा पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर क्रमशः 5.6, 6.3 तथा 7.0 प्रतिशत रही। कृषि (4.5 प्रतिशत), विनिर्माण (9.1 प्रतिशत) और निर्माण (11.5 प्रतिशत) क्षेत्रों के उल्लेखनीय योगदान से ही यह शानदार प्रदर्शन संभव हो पाया।

वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में क्षेत्रवार स्तर पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के लिए स्थिर (2011-12) मूल्यों पर जीवीए वृद्धि दर क्रमशः 4.5, 8.8 और 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया। वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में पूंजीगत सामान की 9.0 प्रतिशत की वृद्धि दर की बदौलत स्थिर मूल्यों पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण की वृद्धि दर चौथी तिमाही में बढ़कर 14.4 प्रतिशत हो गई, जबकि पहली, दूसरी और तीसरी तिमाहियों में यह वृद्धि दर क्रमशः 0.8, 6.1 तथा 9.1 प्रतिशत थी।

राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमानों के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 के लिए स्थिर (2011-12) मूल्यों पर जीडीपी वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2017-18 में क्षेत्रवार स्तर पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के लिए स्थिर (2011-12) मूल्यों पर जीवीए वृद्धि दर क्रमशः 3.4, 5.5 और 7.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया ।

स्थिर (2011-12) और वर्तमान मूल्यों पर वित्त वर्ष 2017-18 की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही की जीडीपी वृद्धि दरों का भी उल्लेख निम्न हैः

जीडीपी वृद्धि दरें

	स्थिर मूल्य (2011-12)	वर्तमान मूल्य
वार्षिक 2017 -18	6.7	10.0
पहली तिमाही, 2017-18 (अप्रैल-जून)	5.6	8.3
दूसरी तिमाही, 2017-18 (जुलाई-सितंबर)	6.3	9.5
तीसरी तिमाही, 2017-18 (अक्टूबर-दिसंबर)	7.0	11.0
चौथी तिमाही, 2017-18 (जनवरी-मार्च)	7.7	10.9

वर्ष 2017-18 में स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वास्तविक जीडीपी अथवा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के बढ़कर 130.11 लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान लगाया गया, जबकि वर्ष 2016-17 के लिए प्रथम संशोधित अनुमानों में यह 121.96 लाख करोड़ रुपये आंका गया था। यह 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता है।

बुनियादी मूल्यों पर सकल मूल्य वर्द्धित (जीवीए)

वर्ष 2017-18 में बुनियादी स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वास्तविक जीवीए बढ़कर 119.76 लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान लगाया गया, जो वर्ष 2016-17 के प्रथम संशोधित अनुमानों में 112.48 लाख करोड़ रुपये था। यह 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता है।

जिन क्षेत्रों ने 7.0 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि दर दर्ज की है उनमें 'लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं (10.0 प्रतिशत)', 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से जुड़ी सेवाएं (8.0 प्रतिशत)' और 'विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं (7.2 प्रतिशत)' शामिल हैं। 'कृषि, वानिकी एवं मत्यपालन', 'खनन एवं उत्खनन', 'विनिर्माण', 'निर्माण' और 'वित्तीय, अचल संपत्ति एवं प्रोफेशनल सेवाओं' की वृद्धि दर क्रमशः 3.4, 2.9, 5.7, 5.7 और 6.6 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया।

सकल राष्ट्रीय आय

वर्ष 2017-18 के दौरान वर्ष 2011-12 के मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) 128.64 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह अनुमानित 120.52 लाख करोड़ रुपये थी। वृद्धि दरों की दृष्टि से वर्ष 2017-18 के दौरान सकल राष्ट्रीय आय में 6.7 फीसदी की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया, जबकि वर्ष 2016-17 के दौरान वृद्धि दर 7.1 फीसदी थी।

प्रति व्यक्ति आय

वर्ष 2017-18 के दौरान सही अर्थों में (2011-12 के मूल्यों पर) प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 86,668 रुपये के स्तर पर पहुंच जाने की संभावना है, जो वर्ष 2016-17 में 82229 रुपये थी। वर्ष 2017-18 के दौरान प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 5.4 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया, जो पिछले वर्ष 5.7 फीसदी थी। ■

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एवं दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के फेज़-1 का शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 मई को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दो नवनिर्मित एक्सप्रेसवे देश के नाम समर्पित किये। इनमें से पहला निज़ामुद्दीन सेतु से दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा तक विस्तृत 14 लेन वाले अभिगम नियंत्रित दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का प्रथम चरण है। राष्ट्रीय राजमार्ग का 8.360 किमी का यह हिस्सा लगभग 841.50 करोड़ रुपये की लागत से 30 महीनों की अपेक्षित निर्माण अवधि के मुकाबले 18 महीनों के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया। इसमें 6 लेन का एक्सप्रेसवे और 4प्लस4 की सर्विस लेन शामिल है। इस परियोजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 31.12.2015 को किया गया था।

दरअसल, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना का लक्ष्य दिल्ली एवं मेरठ के बीच तथा इससे और आगे, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के साथ तेज एवं सुरक्षित संपर्क उपलब्ध कराना है। परियोजना की कुल लंबाई 82 किमी है, जिसमें से प्रारंभ की 27.74 किमी की लंबाई 14 लेन होगी, जबकि शेष 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। इस परियोजना पर 4975.17 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। यह ऐसा पहला एक्सप्रेसवे होगा, जिसमें दिल्ली एवं डासना के बीच लगभग 28 किमी के खंड पर समर्पित साईकिल ट्रैक होगा। इस परियोजना में 11 फ्लाईओवरों/इंटरचेंज, 5 बड़े एवं छोटे पुल, तीन रेल ओवरब्रिज, 36 वाहनों के लिए तथा 14 पैदल यात्रियों के लिए अंडरपास होंगे। पूरी परियोजना के संपन्न हो जाने के बाद दिल्ली से मेरठ जाने में केवल 60 मिनट लगेंगे।

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे

देश के नाम समर्पित दूसरी परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर कुंडली से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर पलवल तक विस्तृत 135 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) है। गौरतलब है कि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (डब्ल्यूपीई) एवं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) से निर्मित दिल्ली के चारों ओर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की परियोजना की परिकल्पना- ऐसे ट्रैफिक को डायवर्ट करके जिनका गंतव्य दिल्ली नहीं हैं; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को भीड़भाड़ एवं प्रदूषण से बचाने के लिए की गई है।

ईपीई के लिए लगभग 5900 करोड रुपये की लागत से कुल 1700 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया। परियोजना की निर्माण लागत लगभग 4617.87 करोड़ रुपये है। एक्सप्रेसवे लगभग 500 दिनों के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया, जबकि निर्धारित लक्ष्य 910 दिनों का था। एक्सप्रेसवे में 4 बड़े पुल, 46 छोटे पुल, तीन

फ्लाईओवर, 7 इंटरचेंज, 221 अंडरपास, 8 आरओबी एवं 114 पुलिया (कल्वर्ट) हैं। इस परियोजना ने लगभग 50 लाख मानव दिवसों के लिए रोजगार की संभावनाएं सृजित की हैं।

यह देश का ऐसा पहला एक्सप्रेसवे है जिसमें पूरी 135 किमी की लंबाई में सौर बिजली का उपयोग किया गया है। अंडरपासों को रौशन रखने वॉटरिंग प्लांटों के लिए सौर पंपों के परिचालन के लिए इस एक्सप्रेसवे पर 4000 किलोवॉट (4 मेगावॉट) की क्षमता के आठ सौर बिजली संयंत्र हैं। ईपीई पर प्रत्येक 500 मीटर पर वर्षा जल संचयन का प्रावधान किया गया है तथा पूरे ईपीई पर ड्रिप सिंचाई भी है। भारतीय संस्कृति एवं विरासत को प्रदर्शित करती स्मारकों की 36 प्रतिकृतियां भी हैं।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के शुभारंभ के बाद प्रधानमंत्री ने राजमार्ग के परीक्षण के लिये कुछ किलोमीटर तक खुली जीप में यात्रा की, इस अवसर पर बागपत में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का समूचा प्रसार जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिल्ली में यातायात की भीड़भाड़ कम करने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के जीनव स्तर को उन्नत बनाने में आधुनिक अवसंरचना की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सड़कों, रेलवे, जलमार्गों इत्यादि समेत ढांचागत व्यवस्था के निर्माण में उठाये जा रहे कदमों का उल्लेख किया। साथ ही, सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अवसंरचना विकास की गति में वृद्धि की भी चर्चा की। ■

मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ परिवारों को 5.75 लाख करोड़ रुपये का मिला ऋण

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 12 करोड़ परिवारों को 5.75 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया। श्री मोदी ने यह बात देश के मुद्रा योजना लाभार्थियों के साथ 29 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद के दौरान कही। दरअसल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने अब तक 5.75 लाख करोड़ रुपये की राशि के 12 करोड़ लोगों को ऋण प्रदान किये हैं। इसमें से 3.25 लाख करोड़ रुपये के ऋण का 28 प्रतिशत पहली बार इस योजना का लाभ उठाने वाले उद्यमियों को प्रदान किये गए। कुल लाभार्थियों में 74 प्रतिशत महिलाओं और 55 प्रतिशत ऋण अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को प्रदान किये गये।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लाभार्थियों से बातचीत करते हुए मुद्रा योजना को रोजगार सृजन वाली योजना बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल ने उद्यमियों को साहूकारों और बिचौलियों के कुचक्र से बचाने में सहायता प्रदान की है। इस योजना ने नया व्यापार आरंभ करने अथवा बढ़ाने की इच्छा रखनेवालों युवाओं और महिलाओं को एक सुअवसर प्रदान किया हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुद्रा योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना ने लघु और सूक्ष्म व्यापार को बढ़ावा देते हुए गरीबों के जीवन में निरंतर सुखद परिवर्तन किया है। इस योजना ने लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया है और लोगों को सफलता के लिए एक मंच प्रदान किया है।

स्वरोजगार सृजन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि स्वरोजगार आज एक गर्व का विषय है और इसने लोगों को उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता की है, जिन्हे पहले असंभव माना जाता था।

संवाद के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि यदि मुद्रा योजना कुछ वर्ष पहले कार्यान्वित की गई होती, तो इससे लाखों लोगों को अपना व्यापार स्थापित करने में मदद मिलती और इससे बड़े स्तर पर पलायन को रोका जा सकता था। प्रधानमंत्री से संवाद करते हुए लाभार्थियों ने मुद्रा योजना से व्यापार स्थापित करने और दूसरों के

लिए रोजगार सृजन करने में सहायता के संबंध में बताया।

गौरतलब है कि 8 अप्रैल 2015 को शुभारंभ हुई इस योजना के अंतर्गत गैर व्यवसायी, गैर कृषि और छोटे व्यापारियों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ये सभी ऋण पीएमएमवाई के अंतर्गत मुद्रा ऋण के नाम से वर्गीकृत किये गये हैं। ये ऋण व्यवसायिक बैंकों, आरआरबी के लघु वित्त बैंकों, सहकारिता बैंकों, एमएफआई और एनबीएफसी के द्वारा प्रदान किये गये हैं। ■

कमल संदेश अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

उद्योग

| दीनदयाल उपाध्याय |

औद्योगीकरण की आवश्यकता

कृषि के उपरांत हमें उद्योगों का विचार करना होगा। भारत का औद्योगीकरण सभी दृष्टियों से आवश्यक है। बिना इसके खेती पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या नहीं घटाई जा सकती। कृषि पर अधिक भार होने के कारण ही नहीं, अपितु उसका योग्य विकास करने तथा सभी व्यक्तियों को पूरा काम देने के लिए लोगों को उद्योग-धंधों में जुटाना नितांत आवश्यक है। अभी तक भारत कच्चा माल पैदा करता रहा तथा पक्के माल के लिए विदेशों पर निर्भर रहा। फलतः वह कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, विशेषकर मंदी के दिनों में उसे भारी संकटों का सामना करना पड़ा। प्राचीन शास्त्रकारों ने वाणिज्य, शिल्प एवं उद्योगों के संबंध में यह लिखा है कि उन्हें अपरमात्रिक होना चाहिए। अर्थात् किसी आवश्यक वस्तु के लिए उन्हें दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। हां, देश के उद्धर्त माल को बाहर निकालने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उपयोग होना चाहिए। उस स्थिति में अपने देश की चीजों को अत्युत्तम बनाने का प्रयास होगा, जिससे उनकी बाहर खपत हो सके। जहां अपने यहां के उद्योगों को टिकाने के लिए जैसे भारत के कपड़े की मिलों को चलाए रखने के लिए मिस्र की रुई, अथवा माल के उद्धर्त न होते हुए भी देश के लोगों को उपभोग से वंचित करके जैसे आजकल शक्कर, खली, ज्वार आदि का भारत से निर्यात, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आवश्यक अंग हो जाए, वह देश कभी 'अपरमात्रिक' नहीं बन पाता। उसकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं चल सकती। सुरक्षा की दृष्टि से भी अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र व युद्ध सामग्री तैयार करने के लिए हमें उद्योगों का विकास करना होगा।

विचारणीय उपादान

औद्योगिक नीति का विचार करते समय हमें श्री मो. विश्वेश्वरैया के अनुसार इन सात बातों का विचार करना चाहिए-(1) Men (2) Material (3) Money (4) Machinery (5) Management (6) Motive power (7) Market अर्थात् (1) मनुष्य (2) माल (3) मुद्रा (4) मशीन (5) प्रबंध (6) शक्ति और (7) मांग। इन सातों का ठीक-ठीक मेल बिठाए बिना यदि हमने उद्योग-धंधे प्रारंभ किए तो वे चल नहीं पाएंगे। ये सातों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि इनमें से एक में भी बदल किया तो फिर दूसरों में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। जो मनुष्य एक साधारण छापे की मशीन पर काम कर सकता है। वह 'रोटरी' पर उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। जो गाड़ी बैल से चलाई जा सकती है, वह पेट्रोल से नहीं चल सकती। जहां धोतियों के लिए बाजार है, वहां फ्रॉक बनाना बुद्धिमानी नहीं होगी। जिसके पास केवल दस हजार रुपए हैं, वह एक लाख की मशीन लगाकर उद्योग प्रारंभ नहीं कर सकता। जो दस आदमियों के एक छोटे से कारख़ाने की देखभाल कर सकता है, वह दस हज़ार आदमियों की मिल का प्रबंधक नहीं बन सकता। जहां पत्थर मिलता ही न हो, वहां पत्थर कूटने की मशीन लगाना निरी मूर्खता ही होगी।

सामाजिक उद्देश्य

उपर्युक्त सातों उपादानों का मेल बिठाते समय कई बार उनमें से एक या दो को आधार मानकर शेष को उनके अनुरूप बदलना पड़ता है। कई बार हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, इसका विचार करके भी इनमें से एकाधिक को प्रमुखता देनी होती है। उदाहरणार्थ, जहां हमें किसी-न-किसी प्रकार से बहुत मात्रा में थोड़े समय में कोई माल तैयार करना है, जैसे लड़ाई के काल में, वहां हम ऐसी मशीन लगाएंगे, जो अधिक उत्पादन कर सके।

किंतु जब हम प्रत्येक व्यक्ति को काम देना ही अपना लक्ष्य रखते हों तो हमें श्रम बचाने वाली मशीनों की आवश्यकता नहीं होगी।

किसी उद्योग के स्वरूप का जब एक व्यक्ति विचार करता है तो वह यही देखता है। कि सभी उपादानों का इस प्रकार उपयोग किया जाए कि उत्पादित माल बाजार में सस्ता एवं अच्छा होने के साथ प्रतिस्पर्धा में टिक सके। उसके इस प्रयास में अन्य व्यक्तियों और उद्योगों पर कौन सा परिणाम होता है, उसकी वह चिंता नहीं करता। किंतु इस ओर प्रथम प्रयास करने वालों को सदैव ही उन लोगों से कठिन संघर्ष लेना पड़ता है, जो पहले से उस क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाकर बैठे हैं। उसका सामर्थ्य जब कम पड़ता है तो वह समाज से सहायता की याचना करता है। विभिन्न देशों की संरक्षण नीतियों का जन्म इसमें से ही हुआ। यह आश्चर्य का विषय है कि जो संरक्षण के सहारे बढ़े, वे दूसरों को उनके मुक़ाबले में संरक्षण दिया जाता है तो विरोध करते हैं। समाज को अपनी उद्योगनीति का निर्धारण व्यापक सामाजिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के हित में करना होगा। हमने इसके पूर्व ही यह निश्चित किया है कि हमारे सामाजिक लक्ष्य राष्ट्र की सुरक्षा सामर्थ्य को बढ़ाना, उपभोग एवं उत्पादक वस्तुओं की वृद्धि, प्रत्येक को काम, न्यूनतम जीवन स्तर की आवाप्ति, विषमताओं की कमी

तथा विकेंद्रीकरण हैं। खुले व्यापार तथा उन्मुक्त प्रतिस्पर्धा के आधार पर हम देश के उद्योग-धंधों को बढ़ा नहीं पाए हैं। राज्य का संरक्षण तथा स्वदेशी भावनाओं के सहारे जन-बल का संरक्षण प्राप्त करके ही देश के कुछ उद्योग-धंधे बढ़े हैं। आज जब हम सर्वांगीण विकास का विचार करते हैं तो संरक्षण की अनिवार्यता को स्वीकार करके चलते हैं। यह संरक्षण देश में उद्योगों को विदेशी उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से तथा देश में छोटे उद्योगों को बड़ों की प्रतिस्पर्धा से देना होगा।

विद्यमान उद्योग

औद्योगिक नीति का विचार करते समय यह भी ध्यान में रखना होगा कि हम आज एक कोरी स्लेट पर नहीं लिख रहे हैं। देश में पहले से कुछ उद्योग-धंधे चल रहे हैं। उनमें जहां एक ओर पूरी तरह संगठित एवं अद्यतन प्रविधियों का उपयोग करने वाले उद्योग हैं, तो दूसरी ओर पुराने चले आने वाले असंगठित एवं अर्धविकसित उद्योग हैं। हमें अपनी नीति का निर्धारण इन सबका विचार करके करना होगा। विशेषकर जब हम कोई नई तकनीक अपनाते हैं तो उसका परिणाम पुरानी इकाइयों पर भी पड़ता है। एक ओर नई मशीनों के लिए सब प्रकार की व्यवस्था करनी होती है तो दूसरी ओर पुराने धंधे में लगी पूंजी बेकार हो जाती है। नए कारख़ानों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव होता है तो दूसरी ओर पुराने कारीगरों को काम नहीं मिलता। जहां एक ओर अपने कारख़ानों को चलाने के लिए बाहर से कच्चा माल तथा उत्पादक वस्तुएं मंगानी पड़ती हैं, वहां दूसरी ओर देश के कच्चे माल के लिए बाजार नहीं रहे। यह सब हमारी असुविचारित उद्योग नीति के कारण है। हमने पश्चिम की तकनीकी प्रक्रिया का आंख बंद करके अनुकरण किया है। हमारे उद्योगों का स्वाभाविक विकास नहीं हो रहा है। वे हमारी अर्थव्यवस्था के अभिन्न एवं अन्योन्याश्रित अंग नहीं, अपितु ऊपर से लादे हुए हैं। उनका विकास या तो विदेशी उद्योगपतियों द्वारा विदेशी माल के देश में विधायन के निमित्त शाखा खोलने, या देश के ही कच्चे माल को विदेशी हितों और पद्धतियों से तैयार करने अथवा विदेशियों के अनुकरणशील सहयोगी अथवा अभिकर्ता कतिपय देशी व्यापारियों द्वारा हुआ है। यही कारण है कि भारत के उद्योगपतियों में सबके सब व्यापारी, आढ़तिया तथा सटोरियों में से आए हैं। उद्योग एवं शिल्प में लगे हुए कारीगरों का विकास नहीं हुआ है।

नई प्रौद्योगिकी की आवश्यकता

देश के उपलब्ध उपादानों के अनुरूप उत्पादन प्रक्रिया का निर्धारण एवं विकास हमारी सबसे बड़ी समस्या है। श्री एम.एस. ठक्कर ने मद्रास में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सभापति पद से बोलते हुए कहा था, "अभी तक हमने बाहर के देशों से स्फूर्ति ली है। हमने मशीनों, कारख़ानों, तज्ञों तथा कारीगरों का आयात किया है। शायद यह उन परिस्थितियों में आवश्यक हो। परिणाम यह हुआ कि भारत में जो बड़े यांत्रिक उद्योग स्थापित हुए हैं, वे दूसरे देशों की नक़ल भर हैं। देशी आविष्कारों पर विकसित उद्योग कदाचित् ही मिलेंगे। हमें पश्चिम से बड़ी उदारता से सहायता मिलेगी। हम ज्ञान, विज्ञान एवं सौहार्द को जहां से भी वह मिलेगा लेंगे, किंतु प्रत्येक पुष्प से मधु लेकर भी शहद में परिवर्तित करने वाली मधुमक्षिका की भांति हमें संपूर्ण प्राप्त सहायता को अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों के अनुरूप ढालकर देश में औद्योगीकरण के ऐसे ढांचे का विकास करना होगा, जिसे हम अपना कह सकें। यह भारत के वैज्ञानिक एवं प्राविधिकों के ऊपर दायित्व है।'' यह चुनौती है, जो हमें स्वीकार करनी चाहिए।

भारत में जब उपलब्ध साधनों का विचार करते हैं तो हम निश्चित ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारी उत्पादन प्रक्रिया श्रम प्रधान होनी चाहिए। हमारे पास प्रथम तो पूंजी की कमी है और जो कुछ हम बचा पाते हैं, उसे जब हम श्रम बचत की योजनाओं के आधार पर अचल पूंजी के रूप में परिवर्तित करते हैं तो वह विदेशों में चली जाती है तथा उसका हमें वास्तविक लाभ कम हो पाता है। इसके अतिरिक्त हमारे पुराने औजार और मशीनें बेकार हो जाती हैं, जिससे पूंजी विनाश (Decapitalization) तथा बेकारी (Disemployment) तेजी से बढ़ते जाते हैं। इस बढ़ी हुई बेकारी के कारण देश में अधिकांश लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठने के बजाय घटता है। पश्चिमी ढंग की तथा बहुत ही गूढ़ (Complex) उत्पादन प्रणाली से थोड़े बहुत लोगों को काम अवश्य मिल जाता है, किंतु देश में वह गतिशील प्रक्रिया उत्पन्न नहीं हो पाती, जो अर्थव्यवस्था को बदलकर समाज में गहरे एवं क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके। यदि हमें ऐसी उद्योग व्यवस्था क़ायम करनी है, जो कृषि के साथ सुसंबद्ध हो सके तथा कृषि से भार कम कर सके तो उसके लिए बड़े उद्योगों के स्थान पर छोटे उद्योगों को प्रमुखता देनी होगी। थोड़े लोगों तथा सरल औजारों के साथ छोटी-छोटी इकाइयां ही आज की परिस्थिति में हमारे लिए सर्वोत्तम हैं। देश की तथा समाज की संपूर्ण अवस्था की आर्थिक क्षेत्र में इसी रूप में अभिव्यक्ति हो सकती है। अर्थात् हमें जो कुटीर एवं छोटे-छोटे उद्योग चल रहे हैं तथा जो कारीगर उनमें काम कर रहे हैं, उन्हें आधार बनाकर उनके विकास की व्यवस्था करनी चाहिए। बहुधा यह देखा जाता है कि छोटे उद्योगों की सहायता के नाम पर कुछ ग्रामोद्योगों (जिन्हें कांग्रेस ने अपने रचनात्मक कार्यक्रम में सम्मिलित किया था) सहायता दे दी जाती है। वे अनुदानों पर निर्भर रहकर किसी-न-किसी प्रकार जीवित रहते हैं। आवश्यकता तो यह है कि उन्हें औद्योगिक कार्यक्रम का आधार बनाकर उनका विकास किया जाए। उनमें एक स्वयं की शक्ति उत्पन्न करनी होगी। कई बार शौक़िया भी कुछ ऐसे लोगों को, जिनका उनसे कभी संबंध नहीं रहा, ग्रामोद्योगों में प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। यह धन का अपव्यय है।

जब हम बड़े उद्योगों का विरोध करते हैं तो मशीन का विरोध नहीं करते। हां, उसकी मर्यादाएं अवश्य अनुभव करते हैं। आज शासन की उद्योग नीति में विशालकाय। बड़े उद्योग तथा चरखा जैसे छोटे ग्रामोद्योग ही आते हैं। वे छोटे-छोटे उद्योग, जो आज की जीवन की अनेक आवश्यकताओं को आधुनिक उत्पादन पद्धति से पूरा करते और कर सकते हैं, अभी तक उपेक्षित हैं। ■

('भारतीय अर्थ-नीति विकास की एक दिशा' से साभार)

प्रखर देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

(6 जुलाई, 1901– 23 जून, 1953)

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी महान शिक्षाविद्, चिन्तक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। भारतवर्ष की जनता उन्हें एक प्रखर राष्ट्रवादी के रूप में जानती है। देश के करोड़ों लोगों के मन में उनकी एक निरभिमानी, देशभक्त की छबि अंकित है। वे आज भी बुद्धजीवियों और मनीषियों के आदर्श हैं। वे अब भी लाखों भारतवासियों के मन में एक पथ-प्रदर्शक एवं प्रेरणापुंज के रूप में समाए हुए हैं।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अनुभवी राजनीतिज्ञ थे। उनके ज्ञान, प्रतिभा और स्पष्टवादिता के कारण उनके मित्र और शत्रु सभी उनका आदर करते थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत ने स्वतंत्रता के शुरुआती चरण में ही एक महान सपूत खो दिया।

डॉ. मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई, 1901 को एक प्रसिद्ध बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता सर आशुतोष बंगाल के एक जाने-माने व्यक्ति थे। डॉ. मुखर्जी ने कलकत्ता से स्नातक डिग्री प्राप्त की। वे 1923 में सीनेट के सदस्य (फैलो) बन गये। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन् 1924 में कलकता उच्च न्यायालय में एडवोकेट के रूप में नाम दर्ज कराया। बाद में, वे सन् 1926 में 'लिंकन्स इन' में अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए और 1927 में बैरिस्टर बन गए।

वे तैंतीस वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय में विश्व के सबसे कम उम्र के कुलपति बने और सन् 1938 तक इस पद पर आसीन रहे। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए कांग्रेसी उम्मीदवार के रूप में बंगाल विधान परिषद् के सदस्य चुने गए, लेकिन उन्होंने अगले वर्ष इस पद से उस समय त्यागपत्र दे दिया, जब कांग्रेस ने विधानमंडल का बहिष्कार कर दिया था। बाद में उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और निर्वाचित हुए।

पंडित नेहरू ने उन्हें अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया। डॉ. मुखर्जी ने लियाकत अली खान के साथ दिल्ली समझौते के मुद्दे पर 6 अप्रैल, 1950 को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। श्री मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री गुरू गोलवलकर जी से परामर्श करने के बाद 21 अक्तूबर, 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की नींव रखी और वे इसके पहले अध्यक्ष बने। सन् 1952 के चुनावों में भारतीय जनसंघ ने संसद की तीन सीटें जीतीं, जिनमें से एक सीट पर श्री मुखर्जी जीतकर आए थे। उन्होंने संसद के भीतर राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी बनायी, जिसमें 32 सदस्य लोकसभा तथा 10 सदस्य राज्यसभा से थे।

डॉ. मुकर्जी जम्मू-कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। उस समय जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा था, अलग संविधान था, वहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाता था। डॉ. मुकर्जी ने जोरदार नारा बुलंद किया कि - एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।

संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण में डॉ. मुकर्जी ने धारा-370 को समाप्त करने की भी जोरदार वकालत की थी। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में स्पष्ट रूप से कहा कि जम्मू-कश्मीर को भारत से काटने की साजिश रची जा रही है। पंडित नेहरू ने डॉ. मुखर्जी पर ही संदेह व्यक्त कर दिया। कोई भी समझौता अथवा रास्ता दिखाई न

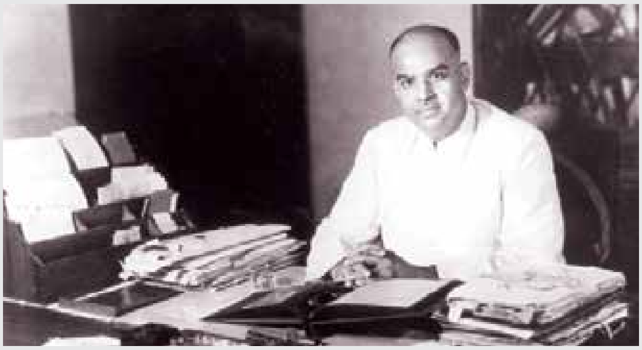

देने पर डॉ. मुखर्जी ने बिना परमिट जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने का फैसला कर लिया। उनकी इस घोषणा में देश की अखंडता के लिए बलिदान देने की उमंग स्पष्ट झलकती थी।

9 मई, 1953 को प्रातः 6.30 बजे डॉ. मुखर्जी रेलगाड़ी से अपने चंद साथियों के साथ जम्मू के लिए रवाना हुए, परंतु जब वे अपने साथियों सहित जम्मू की सीमा रावी नदी के किनारे लखनपुर पहुंचे तो कश्मीर मिलिशिया पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 23 जून, 1953 को संदिग्ध परिस्थितियों में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो गई। सच तो यह है कि डॉ. मुखर्जी ने भारत विरोधी, विघटनकारी और पाकिस्तानपरस्त शक्तियों से लोहा लिया। वे भारत मां के मुकुट कश्मीर को पाकिस्तानी शिकंजे में जाने से रोकने में सफल हुए। अखंड भारत के लिए वीरगति प्राप्त करने वाले शहीद डॉ. मुखर्जी ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि भारत की जनता और नेता एकजुट होकर पूरी ताकत से देशद्रोहियों का प्रतिकार करें, तो विदेश प्रेरित शक्तियां अवश्य परास्त होंगी। ■

प्रधानमंत्री द्वारा झारखंड में 27,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 मई को सिंदरी में आयोजित एक समारोह में भारत सरकार और झारखंड सरकार की 27,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के सिंदरी उर्वरक परियोजना का पुनरुद्धार, गेल द्वारा रांची सिटी गैस वितरण परियोजना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), देवघर, देवघर हवाई अड्डे का विकास और पतरातू सुपर थर्मल पावर परियोजना शामिल हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जन-औषधि केंद्रों के लिए सहमति पत्रों का आदान-प्रदान भी किया गया।

प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार झारखंड के तीव्र विकास के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज 27,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि इन विकास परियोजनाओं से झारखंड के युवाओं को अवसर प्राप्त होंगे।

उन्होंने कहा कि जब मैंने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया उस समय 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी। श्री मोदी ने कहा कि हमने इन गांवों के ग्रामीण लोगों के जीवन में उजाला लाने का काम किया और वहां बिजली पहुंचाई। श्री मोदी ने कहा कि हमने एक कदम आगे बढ़कर सुनिश्चित किया कि भारत में प्रत्येक घर तक बिजली की पहुंच हो।

उन्होंने कहा कि जिन उर्वरक संयंत्रों काम रुका हुआ था, वहां फिर से काम शुरू हो गया। श्री मोदी ने कहा कि पूर्वी भारत को इसका सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड में एम्स की स्थापना से स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में व्यापक बदलाव होगा और गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने हवाई यात्रा को सुगम और किफायती बनाया है। ■

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पतरातू सुपर थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 मई को झारखंड में एनटीपीसी की पतरातू सुपर थर्मल पावर परियोजना के 2400 मेगावाट वाले प्रथम चरण की आधारशिला रखी। यह झारखंड सरकार और एनटीपीसी की एक सहायक कंपनी पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पीवीयूएनएल) के बीच 74:26 प्रतिशत की हिस्सेदारी वाला संयुक्त उद्यम है। इसके तहत 4000 मेगावाट का कुल क्षमता विस्तार स्थापित किया जाएगा। इस अवसर पर केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर.के. सिंह और झारखंड एवं केन्द्र के अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

दरअसल, पीवीयूएनएल दो चरणों में इस परियोजना को क्रियान्वित करेगी। प्रथम चरण में 2400 मेगावाट (3x800 मेगावाट) और दूसरे चरण में 1600 मेगावाट (2x800 मेगावाट) बिजली का उत्पादन किया जाएगा। दूसरे चरण को बाद में क्रियान्वित किया जाएगा। इस परियोजना के तहत 85 प्रतिशत बिजली झारखंड को आवंटित की जाएगी, जिससे आगे चलकर यह राज्य लाभान्वित होगा और इसके साथ ही इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत यह परियोजना घरों में चौबीसों घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

इस परियोजना के लिए इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण ठेका भेल को दिया गया है। पहली यूनिट वर्ष 2022 तक चालू होने की परिकल्पना की गई है और इसके बाद छह-छह महीने के अंतराल पर अन्य दो यूनिटों को भी चालू किया जाएगा।

चूंकि एनटीपीसी आसपास के समुदायों का जीवन स्तर बेहतर करने पर फोकस करते हुए समावेशी विकास और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पीवीयूएनएल पहल से ही स्वच्छ पेयजल एवं नियमित स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था करने के साथ-साथ निकटवर्ती गांवों में स्थानीय युवाओं के कौशल विकास पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करती रही है। परियोजना का काम आगे बढ़ने के साथ ही समुदाय विकास के तहत रोजगार क्षमता बढ़ाने, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, बुनियादी ढांचे के विकास एवं बालिकाओं की शिक्षा पर भविष्य में और ज्यादा फोकस किया जाएगा।

एनडीए सरकार के चार साल पूरे होने पर मेरी राय

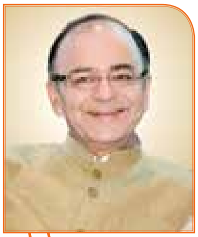

अरुण जेटली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली एनडीए सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल को पूरा करके पांचवे साल में प्रवेश कर चुकी है।

बदलाव

यूपीए सरकार के बीते दस वर्षों के शासन को निर्विवाद रुप से आजादी के बाद की सबसे भ्रष्टतम सरकार के रूप में देखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधायी और संस्थागत परिवर्तनों के माध्यम से पारदर्शी प्रणालियों का निर्माण किया जिसके कारण देश को घोटालों से मुक्त सरकार मिली। यूपीए सरकार के विपरीत हमारे प्रधानमंत्री पार्टी और देश दोनों के नेता हैं। हमने सरकार की अनिश्चितता भरी स्थिति से स्पष्टता एवं निर्णय लेने की क्षमता की स्थिति तक पहुंचने की यात्रा को देखा है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्यों में भारत "नाजुक पांच" से "उज्ज्वल पांच" में परिवर्तित हुआ है। नीतिगत अपंगता की स्थिति अब निर्णय लेने और उसके कार्यान्वयन में बदल चुकी है। भारत "निराशा" बनने के कगार पर था, लेकिन आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में बदल गया है। निराशा से देश की मनोदशा आशा और आकांक्षाओं में बदल गई है। अच्छी राजनीति को सुशासन और अर्थशास्त्र के साथ मिश्रित किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि भाजपा अधिक आत्मविश्वासपूर्ण है, इसके भौगोलिक और सामाजिक आधार में काफी वद्धि हुई है, तथा इसकी जीत में भी काफी वृद्धि हुई है। कांग्रेस निराशा में है, इसलिए भारतीय राजनीति की प्रमुख पार्टी से अब यह "क्षेत्रीयता" की ओर बढ़ रही है और राजनीतिक तौर पर यह मुख्यधारा की पार्टी नहीं है, लेकिन आमतौर पर इनकी तुलना "कमजोर" संगठनों के रूप में की जाती हैं। कमजोर संगठन कभी सत्ता में आने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इनका सबसे ज्यादा फायदा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के समर्थक बनने में निहित है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का मानना है कि हाशिए पर पड़ी कांग्रेस केवल एक मामूली समर्थक हो सकती है। कर्नाटक में इसका एक संक्षिप्त उदाहरण देखा गया था। एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल जिसका आधार कुछ जिलों तक सीमित है, ने कांग्रेस से सौदेबाजी कर मुख्यमंत्री पद हासिल कर लिया और कांग्रेस ने भी उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

भ्रष्टाचार मुक्त सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणाली को संस्थागत बनाया है जहां विवेकाधिकार समाप्त हो गए हैं। विवेकाधिकार शक्ति के दुरुपयोग का कारण बनता है, क्योंकि उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। अनुबंध, प्राकृतिक संसाधन, स्पेक्ट्रम और अन्य सरकारी आवंटन, जिसे विवेकाधिकार के तहत वितरित किया जाता था उसे अब बाजार तंत्र के माध्यम से आवंटित किया जा रहा है। पर्यावरण मंजूरी के लिए अब फाइलों का ढेर नहीं लगता है और एफआईपीबी को खत्म कर दिया गया है। अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में अब भारत नॉन कंप्लाइंट वाले समाज से टैक्स कंप्लाइंट वाले समाज में बदल चुका है। माल और सेवा कर का अधिनियमन और कार्यान्वयन को प्रभावी ढंग से अनुपालन करना और काले धन के खिलाफ सभी समुचित कदम उठाना होगा, दिवालियापन संहिता ने ऋणदाता-लेनदार संबंध बदल दिया है। लेनदारों को अब देनदारों का पीछा नहीं करना पड़ता है। यदि आप अपने लेनदारों का भुगतान नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक वैधानिक तंत्र से बाहर निकलना होगा।

सामाजिक क्षेत्र की प्राथमिकता

इतिहास में पहली बार दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन प्रोग्राम के तहत गरीब और समाज के हाशिये वाले वर्ग के लोगों के बैंक खाते खोले गए। कमजोर और वंचित लोगों के लिए मुद्रा योजना के तहत लोन लेने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इसके सबसे बड़े लाभार्थियों में महिलाएं, एससी/ एसटी, अल्पसंख्यक और समाज का कमजोर वर्ग है। भारी खर्चों के साथ ग्रामीण सड़कों का निर्माण एक सफल कहानी है। सरकार का इरादा है कि हर गांव तक सड़क की पहुंच, बिजली की उपलब्धता, किफायती आवास की सुविधा, टॉयलेट और सभी घरों को गैस कनेक्शन देना है। फसल बीमा योजना और सरकार का यह निर्णय कि किसानों को 50 प्रतिशत से अधिक लागत मिलनी चाहिए, ये कृषि संकट को खत्म करने के उद्देश्य से हैं। यूपीए सरकार ने मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, लेकिन बजट कटौती कर केवल 29,000 करोड़ रुपये खर्च किए थे। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लोगों को सस्ता अनाज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यय बढ़ाकर 1,70,000 करोड़ रुपये कर

दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी सरकार ने तस्वीर बदलने का काम किया है। हेल्थकेयर भारत के गरीबों की नियति बदलने वाली है। सबसे पिछड़े 40 प्रतिशत परिवार सरकारी योजना की लागत पर अस्पताल में भर्ती के लिए पांच लाख रुपये तक का इलाज करा सकेंगे।

आर्थिक प्रबंधन

यूपीए सरकार के कार्यकाल में भारत वैश्विक राडार से गायब हो गया था। शुरुआती सालों में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था में तेजी थी, तब इसके कारण देश का विकास हुआ। जब वैश्विक स्थितियां बदली तो यूपीए सरकार की निर्णायक क्षमता और प्रदर्शन खत्म हो गया। यूपीए सरकार के आखिरी दो सालों के कार्यकाल में विकास दर में काफी कमी आई है। वहीं एनडीए शासन के पहले साल में भारत तेजी के बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया, जिसकी जीडीपी ग्रोथ रेट उच्चतम थी। चालू खाता घाटा (सीएडी) ने वर्ष 2012-13 में अभूतपूर्व 6.7 प्रतिशत घाटा देखा। एनडीए ने सालाना आधार पर 2 प्रतिशत से कम का सीएडी बनाए रखा है। खराब आर्थिक प्रबंधन तब दिखाई दे रहा था, जब यूपीए राजकोषीय घाटे के तहत खतरनाक उच्च रहा। सरकार अधिक खर्च कर रही थी और कम कमाई कर रही थी। हमने यूपीए के पिछले तीन वर्षों में 5.8 प्रतिशत, 4.8 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत की राजकोषीय घाटे देखा।

साल दर साल गड़बड़ करने के बाद एनडीए ने 3.5 प्रतिशत तक लाया है और इस साल 3.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे रहने का अनुमान है। यूपीए का आर्थिक प्रबंधन ऐसा था कि जब राजकोषीय घाटे बहुत अधिक होता तो राजकोषीय घाटे को थोड़ा बेहतर दिखने के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक व्यय में कटौती की गई थी। व्यय में कटौती का मतलब विकास में कटौती है। एनडीए के शासन के दौरान व्यय के संशोधित अनुमान हमेशा बजट अनुमानों से अधिक थे। यूपीए ने पिछले वर्षों में भारत को 9 प्रतिशत तक मुद्रास्फीति दर प्रदान की और एक चरण में भी दो अंकों के पार हो गया था। एनडीए ने मुद्रास्फीति को काबू करने की कोशिश की और ज्यादातर अवसर 3 से 4 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर बने रहे हैं। यूपीए के खराब आर्थिक प्रबंधन के परिणामस्वरूप केंद्र और राज्य सरकारों के लिए उधार लेने की उच्च लागत हुई। अप्रैल, 2014 में बॉन्ड उपज एक अविश्वसनीय 9.12 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। औसतन, हम एक अवसर पर 6.3 प्रतिशत के निचले स्तर के साथ 6 से 7 प्रतिशत के बीच रखने में सक्षम रहे और शायद ही कभी 7 प्रतिशत रेंज में जब वैश्विक कारकों ने मुद्रा या कच्ची कीमतों को प्रभावित किया।

यूपीए के आखिरी साल से, चालू वर्ष के दौरान इस वर्ष बुनियादी ढांचा व्यय में 134 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष को याद रखना चाहिए कि कर सरकार की जेब में नहीं जाते हैं। वे बेहतर बुनियादी ढांचे, बेहतर सामाजिक क्षेत्र के व्यय और गरीबी में कमी करने कार्यक्रमों के लिए लोगों के पास वापस जाते हैं। सामाजिक क्षेत्र के व्यय में केंद्रीय और राज्य सरकारों दोनों ने काफी वृद्धि की है। यूपीए के अंतिम वर्ष और वर्तमान सरकार के चालू वर्ष के बीच सड़क क्षेत्र के कार्यक्रमों में 189 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। संसाधनों को करों के 42 प्रतिशत विघटन, वित्त आयोग अनुदान और सीएसएस योजनाओं के माध्यम से सहायता के साथ राज्यों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यूपीए शासन के अंतिम साल में राज्यों को 5,15,302 स्थानांतरित किया गया था। इस साल प्रस्तावित स्थानांतरण 145 प्रतिशत अधिक है और 12,62,935 करोड़ रुपए पर होगा है। जीएसटी में राज्यों को 14 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ संवैधानिक रूप से संरक्षित किया गया है। राज्य स्वतंत्र रूप से अपने वसूल करते है। इस प्रकार अधिनियमित और संस्थागत परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मजबूत मजबूत पद पर स्थापित कर रही है।

पांचवें वर्ष पर बहस

चूंकि एनडीए की सरकार पांचवें वर्ष में प्रवेश कर रही इसकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। यह हमारी नीतियों और कार्यक्रमों के एकीकरण का वर्ष होगा जिसे हमने कार्यान्वित किया है। हमारे प्रधानमंत्री में सामूहिक अपील के साथ एक मजबूत नेता के गुण हैं। प्रधानमंत्री के भारत की नियति बदलने की क्षमता को विश्व

यूपीए ने पिछले वर्षों में भारत को 9 प्रतिशत तक मुद्रास्फीति दर प्रदान की और एक चरण में भी दो अंकों के पार हो गया था। एनडीए ने मुद्रास्फीति को काबू करने की कोशिश की और ज्यादातर अवसर 3 से 4 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर बने रहे हैं। यूपीए के खराब आर्थिक प्रबंधन के परिणामस्वरूप केंद्र और राज्य सरकारों के लिए उधार लेने की उच्च लागत हुई।

स्तर पर मान्यता प्राप्त है। प्रधानमंत्री के काम करने की उनकी अविश्वसनीय क्षमता, नीति और दिशा की उनकी स्पष्टता, राष्ट्रीय हित में बड़े कदम उठाने में उनकी बहादुरी एनडीए को राजनीतिक लाभ प्रदान करती है। स्पष्टता और विश्वसनीयता एनडीए सरकार के हॉलमार्क हैं।

पिछले कुछ दिनों में "कल्पित विकल्प" के बारे में चर्चा हुई है। अलग-अलग राजनीतिक दलों का एक समूह एक साथ आने का वादा कर रहा है। उनके कुछ नेता स्वभावतः कभी-कभी अपनी वैचारिक स्थिति बदलते रहते हैं। जैसे टीएमसी, डीएमके, टीडीपी, बीएसपी और जेडी(एस) को बीजेपी के साथ सत्ता साझा करने का अवसर मिला है। वे अक्सर राजनीतिक पाला बदलते रहते हैं। पाला बदलते वक्त दावा करते है की यह राष्ट्रीय हित में है भाजपा का विरोध धर्मनिरपेक्षता के नाम पर करते है। ये वैचारिक रूप से लचीला राजनीतिक समूह हैं। स्थिर राजनीति उनके राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड से बहुत दूर है। इस समूह के कुछ लोगों का एक बेहद संदिग्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। कुछ नेता घुमक्कड़ होते हैं और उन लोगों को शामिल किया जाता है जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के दोषी है। ऐसे कई हैं जिनके राजनीतिक समर्थन आधार को कुछ जिलों या किसी विशेष जाति तक ही सीमित रखा गया है। गठबंधन के माध्यम से भारत जैसे बड़े देश पर शासन करना संभव है, लेकिन गठबंधन के केंद्र को स्थिर होना चाहिए। इसमें एक बड़ा आकार, एक वैचारिक रूप से परिभाषित स्थिति और ईमानदार शासन में निहित हित होना चाहिए। एक संघीय मोर्चा एक असफल विचार है। इसका प्रयोग 1978,1991 एवं 1996-98 के बीच श्री चरण सिंह, श्री चंद्रशेखर और संयुक्त मोर्चा सरकार के तहत किया गया था। विरोधाभासों की वजह से इस तरह का एक मोर्चा, जल्दी या बाद में विघटित हो जाता है। 1996-98 को शासन की सबसे बुरी अवधि के रूप में याद करते हुए, महत्वाकांक्षी भारत जो आज दुनिया में उच्च तालिका पर काबिज है, कभी भी ऐसा विचार स्वीकार नहीं करेगा जो बार-बार विफल रहा। इतिहास हमें यह सबक सिखाता है। जीवंत लोकतंत्र वाले महत्वाकांक्षी समाज अराजकता को आमंत्रित नहीं करते हैं। एक मजबूत राष्ट्र और सुशासन की आवश्यकताएं अराजकता से घृणा करती हैं। इस वर्ष राजनीतिक बहस का एजेंडा प्रधानमंत्री "मोदी बनाम अराजकतावादी संयोजन" होगा। 2014 के चुनाव ने निश्चित रूप से स्थापित किया था कि जब देश की नियति का निर्णय लेने की बात आएगी तो नए भारत का रसायन शास्त्र अंकगणित पर भारी पड़ेगा। ■

(लेखक केंद्रीय मंत्री हैं)

महाराष्ट्र के कृषि मंत्री पांडुरंग फुंडकर का निधन

महाराष्ट्र के कृषि मंत्री श्री पांडुरंग फुंडकर का 31 मई को मुंबई में तड़के चार बजे दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 67 वर्षीय श्री फुंडकर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। वे जुलाई 2016 में देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उससे पहले वे साल 1991 से लेकर 1996 तक दो बार महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष रहे। वह 1978 में पहली बार विधायक चुने गए और साल 1980 में फिर से खमगांव विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे तीन बार अकोला से सांसद चुने गए। श्री फुंडकर महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी रहे।

श्री फुंडकर के निधन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने लिखा कि महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री पांडुरंग फुंडकर के निधन से स्तब्ध हूं। उन्होंने महाराष्ट्र में भाजपा के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह राज्य के किसानों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहे। मेरी संवेदना उनके परिवार और समर्थकों के साथ है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने ट्वीट कर अपनी शोक संवेदना में लिखा कि महाराष्ट्र के कृषि मंत्री पांडुरंग फुंडकर के अचानक निधन की खबर सुनकर बहुत दुःख हुआ। वह तीन बार अकोला से सांसद रहे। भाऊसाहेब फुंडकर राज्य में भाजपा के विस्तार हेतु अनथक कार्य किया। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं।

मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व कृषि मंत्री पांडुरंग फुंडकर का अचानक दुःखद निधन हुआ। इसका हमें दुःख है। उनके निधन से भाजपा परिवार का नुकसान हुआ है। वह राज्य के विकास में एक शिल्पकार के रूप में देखे जाते थे। जिन चंद लोगों ने भाजपा को गांव-गांव तक पहुंचाया उसमें फुंडकर का भी योगदान रहा है। ■

सहयोग से समृद्ध होगा एशिया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई से 2 जून तक इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की सफल यात्रा की। यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के साथ रक्षा सहयोग मजबूत करने समेत 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। मलेशिया में श्री मोदी ने द्विपक्षीय कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर "रचनात्मक चर्चा" की और सिंगापुर के साथ 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।

इंडोनेशिया: 15 समझौतों पर हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 29 मई से 2 जून तक इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की पांच दिवसीय सफल यात्रा के प्रथम चरण में इंडोनेशिया पहुंचे। यहां पर प्रधानमंत्री श्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री जोको विदोदो के बीच वार्ता के बाद दोनों देशों ने समग्र रणनीतिक साझेदारी के लिए अपने संबंधों को और मजबूती प्रदान करने पर सहमति जतायी। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग समेत कुल 15 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।

वार्ता के बाद एक संयुक्त प्रेस बयान में श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने समग्र रणनीतिक साझेदारी के लिए अपने संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जतायी है। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने समुद्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में तीन चर्चों पर हाल में हुए आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की और उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जकार्ता के साथ मजबूती से खड़ा है। श्री मोदी ने राष्ट्रपति श्री जोको विदोदो से बातचीत के बाद एक बयान में कहा कि मित्रों, मैं इंडोनेशिया में हाल के हमलों में निर्दोष नागरिकों की मौत से दुखी हूं। भारत ऐसे हमलों की कड़ी निंदा करता है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इंडोनेशिया के साथ है। श्री मोदी ने कहा कि ऐसी दुखद घटनाएं एक संदेश देती है कि यह समय की जरुरत है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक स्तर पर प्रयास मजबूत किए जाएं।

मलेशिया: रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने पर जोर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इंडोनेशिया से सिंगापुर जाते समय कुछ समय के लिए मलेशिया रुके। वहां पर उन्होंने मलेशिया के नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री श्री महातिर मोहम्मद से 31 मई को मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने पर सकारात्मक चर्चा हुई।

सिंगापुर: आर्थिक, रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाने पर सहमति

यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीन दिवसीय सिंगापुर की सफल यात्रा की। 1 जून को भारत और सिंगापुर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के उनके समकक्ष श्री ली सीन लूंग के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, आर्थिक सहयोग समेत आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साथ ही, उन्होंने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में शांतिपूर्ण, मुक्त तथा दोस्ताना नौवहन वातावरण बनाने की वकालत करते हुए रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।

दोनों नेताओं की उपस्थिति में दोनों देशों के बीच लोक सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, मादक पदार्थ नियंत्रण और दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच एक दूसरे के साजो-सामान और सुविधाओं में सहयोग सहित कई क्षेत्रों में सहमति ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत और सिंगापुर की रणनीतिक साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है।

श्री ली के साथ विस्तृत चर्चा के बाद जारी एक संयुक्त बयान

में श्री मोदी ने कहा हमने विस्तृत आर्थिक सहयोग समझौते की दूसरी समीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, हालांकि हमारे बीच यह सहमति बनी है कि यह सिर्फ हमारा लक्ष्य ही नहीं, बल्कि इसके जरिये हमें नई सफलताओं को हासिल करना है। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी जल्दी ही इस समझौते को बेहतर बनाने और समीक्षा करने पर चर्चा शुरू करेंगे। दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा सहयोग की तारीफ की और दोनो देशों की नौसेनाओं के बीच लाजिस्टिक समझौते का स्वागत किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वक्त में साइबर अपराधों, चरमपंथ और आतंकवाद से निपटना हमारे सहयोग में महत्वपूर्ण होगा। श्री मोदी और श्री ली ने क्षेत्रीय तथा वैश्विक चुनौतियों पर विचारों का आदान-प्रदान किया, समुद्री सुरक्षा पर अपना रुख दोहराया और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जतायी। दोनों नेताओं के बीच मुक्त, स्थिर और स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार माहौल बनाए रखने पर सहमति बनी।

श्री मोदी ने कहा कि हम हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में शांतिपूर्ण, मुक्त और मित्रवत समुद्री परिवेश बनाने पर सहमत हुए। वहीं, प्रधानमंत्री श्री ली ने कहा कि द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत हुए हैं। श्री ली ने कहा कि हमारा रक्षा संबंध मजबूत हुये है, हमारी नौसेनाओं के

बीच लाजिस्टिक क्षेत्र में सहयोग पर आज समझौता हुआ और इस वर्ष सिंगापुर-भारत द्विपक्षीय नौवहन अभ्यास की 25वीं वर्षगांठ भी मनाएंगे।"

श्री मोदी ने कहा कि सिंगापुर हमेशा से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और अन्य देशों में निवेश का स्रोत रहा है। यह भारतीयों के लिए भी पसंदीदा निवेश स्थान रहा है। उन्होंने कहा मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय कंपनियां न सिर्फ इस देश में बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र में निवेश के लिए सिंगापुर को माध्यम बनाया है। सिंगापुर की कंपनियों के लिए भारत के विकसित होने के साथ ही अवसर बढ़ेंगे।

नान्यांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भ्रमण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1 जून को सिंगापुर में नान्यांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। छात्रों के साथ संवाद के दौरान उन्होंने छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए।

21वीं सदी में एशिया के समक्ष चुनौतियों पर आधारित एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अक्सर कहा जाता है कि 21वीं सदी एशिया की सदी होगी। यह आवश्यक है कि हम स्वयं पर भरोसा रखें और हमें यह जानना चाहिए कि अब हमारी बारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अवसर के अनुरूप हमें अपने को तैयार करना चाहिए और हमें इसका नेतृत्व करना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने चीन में राष्ट्रपति श्री जिनपिंग के साथ हुई बैठक का जिक्र किया। उन्होंने राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग को एक दस्तावेज़ सौंपा, जो बताता है कि पिछले 2,000 वर्षों में से 1,600 वर्षों के दौरान वैश्विक जीडीपी में भारत और चीन की सम्मिलित हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक रही है और इसे बिना संघर्ष के हासिल किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें बिना संघर्ष के कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर प्रशासन के क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विशेष भूमिका निभानी है। यह आम लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अवसंरचना विकास के सटीक मानचित्रण में हमारी मदद कर सकता है, जैसे कहां हमें स्कूलों, सड़कों, अस्पतालों आदि की अधिक आवश्यकता है?

परंपरा और वैश्वीकरण में संतुलन से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में श्री मोदी ने कहा कि नवोन्मेष, नैतिकता और मानवीय मूल्यों के आधार पर सदियों से मानवता ने विकास किया है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी मानवीय रचनात्मकता को सहायता प्रदान कर रही है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों ने लाखों लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है।

चौथे औद्योगिक क्रांति के युग में समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यवधान का अर्थ विनाश नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी लोगों को सशक्त बनाती है तथा प्रौद्योगिकी आधारित समाज, सामाजिक बाधाओं को समाप्त करता है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी को सस्ता और उपयोगकर्ता अनुकूल होना चाहिए।

शांग्री–ला वार्ता को संबोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सिंगापुर में एशिया के अहम रक्षा एवं सामरिक मामलों के सम्मेलन शांग्री-ला वार्ता को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि ''प्रतिद्वंद्विता वाले एशिया'' से क्षेत्र पिछड़ जाएगा, जबकि सहयोग वाले एशिया से मौजूदा शताब्दी का स्वरूप तय होगा। गौरतलब है कि श्री नरेंद्र मोदी शांग्री-ला वार्ता को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।

सिंगापुर की यात्रा के आखिरी दिन श्री मोदी ने अमेरिका के रक्षा मंत्री श्री जिम मैटिस से भी मुलाकात की तथा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। वह चांगी नौसैन्य अड्डे भी गए तथा वहां भारतीय नौसेना और रॉयल सिंगापुर नौसैना के अधिकारियों एवं नौसैनिकों से मुलाकात की। ■

देश विकास पथ पर सतत् अग्रसर

भूपेंद्र यादव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के चार वर्ष पूरे हुए हैं। इस कार्यकाल में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां देश की जनता एवं सरकार के मध्य प्रभावी संवाद स्थापित किया, वहीं सरकार के आर्थिक निर्णयों में साहस, गरीब कल्याण कार्यक्रमों के लक्ष्यों की सफलता, सामाजिक विषयों की जागरूकता ने देश के आम नागरिकों के मन में आत्मसम्मान एवं विश्वास का भाव बढ़ाया है। यही कारण है कि विगत चार वर्षों में जन सामान्य की राजनैतिक विषयों में सक्रियता बढ़ी है। देखा जाए तो उत्तर-पूर्व के चुनाव परिणामों से लेकर आम जन के मुद्दे देश की राजनीति की चर्चा के केंद्र बिंदु बने हैं। देश में आमजन की अपेक्षाओं में वृद्धि हुई है, वहीं युवा वर्ग में भारतीयता का भाव प्रभावी हुआ है। भाजपा का विभिन्न राज्यों में विस्तार इस जनभावना के सकारात्मक साथ होने को दर्शाता है।

सरकार के इन चार वर्षों के कार्यकाल को चार विषयों एवं उपलब्धियों में विभाजित करके देखा जा सकता है। पहला सुशासन का विषय देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बना है। दूसरा सामाजिक विषयों पर सरकार एवं जनता का संवाद बढ़ा है। तीसरा समाज के हाशिये पर खड़े वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है। चौथा विश्व में भारत की साख में वृद्धि हुई है।

किसी भी सरकार के सुशासन का पहला मानक होता है कि सरकार की योजनाओं को एक निश्चित कार्यावधि में पूरा किया जाए। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला, उजाला, जन-धन , मुद्रा जैसी योजनाओं को एक निश्चित समय में पूरा किया है। सुशासन का दूसरा मानक है कि शासन की चुनौतियों का साहस के साथ सामना किया जाए और जनता के अधिकतम कल्याण के विषयों पर साहस भरे निर्णय लिए जाएं। केंद्र सरकार ने नोटबन्दी, जीएसटी, काले धन के खिलाफ कड़े कानून के माध्यम से इन पर सख्ती से करवाई की है। सुशासन का तीसरा मानक है कि जड़ता प्राप्त कर चुके कानूनों को समाप्त करके शासनतंत्र में प्रभावी कानूनों एवं नीतियों को लागू किया जाए। इसलिये आधार जैसे कानून के माध्यम से गरीब व्यक्तियों के हक को सुनिश्चित किया गया है। दिवालिया कानून जैसे कानून लाकर विश्व समुदाय में भारत की व्यापारिक साख को व्यवस्था के माध्यम से सुधारने का काम हुआ है। यही कारण है कि आज विश्व व्यापार में भारत की रैंकिंग एक सौ तीस से छलांग लगाकर सौ वें स्थान पर पहुंची है। पहली बार भूषण स्टील का केस एक उदाहरण बना है, जहां बैंकों का पैसा, कर्मचारियों का वेतन और सरकार के पैसे दिवालिया कानून के माध्यम से वापस आये हैं। यह भी सच है कि केंद्र सरकार के सुशासन के हर कदम को हर विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों द्वारा मुद्दा बनाया गया है, परन्तु न तो जनता ने उनका समर्थन किया और न ही किसी कानून को लागू करने के बाद सरकार को पीछे मुड़कर देखना पड़ा। एक तरफ देश में विपक्ष द्वारा धर्म-जातिवाद, सम्प्रदायवाद, वंशवाद की राजनीति का सहारा लेकर बार-बार विभेद पैदा करके जनता को उकसाने का काम किया जा रहा है, परन्तु देश आज सुशासन की राजनीति को ही राजनैतिक दलों की शासन में आने की कसौटी मान रहा है। और इसलिए सुशासन को राजनीति का केंद्र बिंदु बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली उपलब्धि है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जनता के साथ प्रशासनिक

सरकार के इन चार वर्षों के कार्यकाल को चार विषयों एवं उपलब्धियों में विभाजित करके देखा जा सकता है। पहला सुशासन का विषय देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बना है। दूसरा सामाजिक विषयों पर सरकार एवं जनता का संवाद बढ़ा है। तीसरा समाज के हाशिये पर खड़े वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है। चौथा विश्व में भारत की साख में वृद्धि हुई है।

स्तर के औपचारिक संबंध ही नहीं रखे हैं, बल्कि सामाजिक सरोकारों में एवं सामाजिक कुरीतियों से लड़ने में जन भागीदारी को भी बढ़ाया है। इसका सबसे बड़ा उदहारण सरकार के द्वारा शुरू किया गया स्वच्छता का कार्यक्रम है। स्वच्छता पर प्रधानमंत्री जी के आग्रह से आज देश के नागरिकों में सार्वजनिक स्थानों में सफाई का भाव बढ़ा है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसके कारण स्वच्छता को लेकर देश की इच्छाशक्ति मजबूत हुई है। विगत चार वर्षों में योग दिवस जैसे कार्यक्रमों में जन भागीदारी में भारी वृद्धि हुई है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट के प्रति युवाओं की रुचि भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा वैश्विक मंचों पर जिस प्रकार हिंदी का प्रयोग किया गया है, उससे देश के ग्रामीण युवाओं में भी अपनेपन और आत्मविश्वास के भाव की वृद्धि हुई है। भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थलों पर सुरक्षा कानून, मेटरनिटी अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। साथ ही, सैन्य बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिकाओं जैसे विषयों के साथ सामाजिक जीवन में महिलाओं के सक्रिय होने का माहौल बना है। सरकार ने अपनी भूमिका को विगत चार वर्षों में बढ़ा करके न केवल जनता से संवाद स्थापित किया है, बल्कि स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्राम विकास, महिला सुरक्षा जैसे विषयों पर जनता ने सरकार के साथ मिलकर कदम बढ़ाया है। मेरा अनुभव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 'मन की बात' के माध्यम से नौजवानों के करियर, किसानों की कृषि, ग्रामीण क्षेत्र के विकास और सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार आदि विषयों पर बात होने से लोगों में राष्ट्र निर्माण के प्रति भागीदारी व सरोकार की भावना को और बल मिला है।

केंद्र सरकार की तीसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि समाज के हाशिये पर खड़े लोगों का सशक्तिकरण करना है। उज्जवला योजना के तहत जहां गरीब के घरों में गैस सिलेंडर पहुंचाया गया है, वहीं शौचालय का निर्माण कराके एक बड़े वर्ग को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है।

सरकार ने गरीबों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए हैं। पिछले 70 सालों के शासनकाल में कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित रखा। इस बार जब ओबीसी के संवैधानिक आयोग का विषय आया, तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया। इससे कांग्रेस की कुटिल राजनीति उजागर होती है। लोकतंत्र की मजबूती 'सबका साथ सबका विकास' से ही संभव है।

सरकार ने गरीबों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए हैं। पिछले 70 सालों के शासनकाल में कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित रखा। इस बार जब ओबीसी के संवैधानिक आयोग का विषय आया, तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया। इससे कांग्रेस की कुटिल राजनीति उजागर होती है। लोकतंत्र की मजबूती 'सबका साथ सबका विकास' से ही संभव है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्त्व में सरकार ने सुशासन की उस धारणा को विकसित किया है, जिससे देश की अपेक्षाओं में वृद्धि हुई है।

विदेश नीति के मोर्चे पर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व समुदाय में भारत की साख बढ़ी है। सत्ता में आते ही अपने शपथ-ग्रहण के कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क देशों के प्रमुखों को आमंत्रित कर सबके साथ मधुर सम्बन्ध रखने की अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया था। साथ ही, एशिया में भारत के मजबूत नेतृत्व का सन्देश भी इसके द्वारा दिया गया था। अब यह सन्देश एशिया से निकलकर विश्व भर में प्रसारित हो रहा है और विभिन्न वैश्विक मंचों पर यह स्पष्ट हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत देश के रूप में उभर रहा है। इसी वर्ष जनवरी में दावोस के मंच से विश्व के तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी का उद्घाटन भाषण देना विश्व समुदाय में भारत के वर्तमान नेतृत्व की स्वीकार्यता को दर्शाता है। इस भाषण में जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्या पर प्रधानमंत्री मोदी जो स्पष्ट दृष्टिकोण उभरकर सामने आया, उसने विश्व समुदाय के समक्ष यह सिद्ध कर दिया कि अब किसी भी बड़े वैश्विक मसले पर भारत नेतृत्व करने में सक्षम हो चुका है। दूसरी चीज कि इस वक्त भारत के विश्व के सभी देशों से मधुर सम्बन्ध हैं। एशिया की बात करें तो गणतंत्र दिवस पर आसियान देशों के प्रमुखों को आमंत्रित करके प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि एशिया में भारत ही बड़ा भाई है, तो वहीं ब्रिक्स सम्मेलन के जरिये वैश्विक प्रभाव का सन्देश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति ने सफलता के नवीन आयाम स्थापित किए हैं और मोदी विश्व पटल पर एक प्रभावी नेता के रूप में उभरे हैं।

कुल मिलाकर स्पष्ट है कि लोक-कल्याण का विषय हो या राष्ट्रीय सुरक्षा का अथवा राष्ट्रीय गौरव का, सभी मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास पथ पर सतत् अग्रसर है। ■

(लेखक भाजपा राष्ट्रीय महासचिव व सांसद हैं)

मोदी सरकार-आर्थिक एवं सामाजिक जन आन्दोलन

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

मोदी सरकार अपने कार्यकाल के प्रथम चार वर्ष पूरे कर रही है। देश अगले साल आम चुनाव की तैयारी कर रहा है। यह आकलन करने का उपयुक्त समय है कि सरकार अपनी नीतियों और कार्यकर्मों को कितनी सफलता से लागू कर रही है और उसकी वैचारिक सोच समझने का। 2014 के आम चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की जीत भारतीय राजनीति में एक युगांतकारी परिवर्तन था। भारत के मतदाताओं ने मोदी जी को आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और समावेशी विकास के लिए चुना था।

आर्थिक दर्शन: मोदी सरकार वित्तीय रूप से जिम्मेदारी के साथ, सरकारी व्यय की दक्षता में विश्वास रखती है। हमारी नीतियों का जोर समाज के सशक्तिकरण पर हैं। यह विचार 'अंत्योदय' के द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए है। तेज आर्थिक वृद्धि के साथ असमानता की चुनौती को समाप्त करने के लिए सरकार को जिन जिन साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए उनका बेहिचक पालन कर रही है। यह यूपीए सरकार की खैरात की नीति से बिल्कुल विपरीत है।

इसके लिए सरकार के द्वारा बुनियादी ढांचे के खर्च के साथ समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए आवंटन में वृद्धि की आवश्यकता थी। जीडीपी के अनुपात में कर को बढ़ाना और राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य से सरकार ने जीएसटी (GST) लागू किया जो आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार है। जीएसटी के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के द्वारा टैक्स के दायरे को बढ़ाने के साथ पंजीकरण, फाइलिंग, असेसमेंट, और रिफंड सभी कार्यो को ऑनलाइन बिना किसी व्यक्तिगत हस्तक्षेप के आसानी से किया जा सकता है।

सरकार ने नीतिगत फैसला लेकर मुद्रास्फीति राजकोषीय घाटे को नियंत्रित किया। सरकार की योजनाओं का जैसे, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), जन धन खाता, और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आदि कदमों से भ्रष्टाचार पर रोक लगी। बेनामी (shell) कंपनियों का पंजीकरण रद्द करना, विदेशों से द्विपक्षीय कर संधि का पुनर्निर्देशन, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम (IDS) और बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। बैंकिंग चैनलों के माध्यम से व्यापार के लेनदेन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि व्यापार के लेनदेन का पूरा लेखा जोखा पारदर्शी हो जाए।

इन्सॉल्वेसी एवं बैंकरप्सी कोड (IBC) पूंजी बाजार में बैंकों के लिए सबसे बड़े सुधारों में से एक है। इसके कारण डिफॉल्टर कंपनियों के प्रमोटरों को अपनी कंपनियों पर नियंत्रण खोने की वास्तविक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आईबीसी के तहत भूषण स्टील लिमिटेड के एनपीए का सफल निस्तारण बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत ला रहा है। फायनेंसियल रिजोल्यूशन और डिपोजिट इंश्योरेंस (FRDI) विधेयक भी वित्तीय संस्थानों में पारदर्शिता ला सकता है।

यूपीए के समय भारत के भविष्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में निराशा का भाव था। वर्तमान सरकार की विदेश नीति छवि को दूर करने और वैश्विक समुदाय को आश्वस्त करने में सफल रही है कि भारत अपनी वास्तविक क्षमता हासिल करेगा। सरकार की नीतियों की सफलता देश में बढ़ते विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) से होती है।

सामाजिक दर्शन: सामाजिक सोच में मोदी सरकार कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से सामाजिक उत्थान के लिए बड़ी सोच, तेज गति और जन भागीदारी में विश्वास करती है। 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत स्वच्छता अभियान गरीबों को सम्मान का जीवन प्रदान करना है, चाहे उनके धर्म, जाति या लिंग कोई भी हो 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की पहल हमारी बेटियों को अवसर की समानता प्रदान करती है। सरकार ऐसे सभी कार्यकर्मों से जागरूकता और सार्वजनिक भागीदारी लाने में सफल रही है। तीन तलाक़ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में मोदी सरकार का रुख मुस्लिम महिलाओं के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है ।

राजनीतिक दर्शन: 'सबका साथ सब का विकास' समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम करने का श्रेय मोदी सरकार को जाता है।

मोदी सरकार संकीर्ण चुनावी लाभ के लिए कोई काम नहीं करती । इसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार पूरी तरह से संलग्न थी। 2004-2014 की अवधि के दौरान कांग्रेस सरकार ने चुनावी लाभ प्राप्त करने की उम्मीद से भारतीय समाज को बाटने की कोशिश के अंतर्गत 'सांप्रदायिक हिंसा विधेयक' को पारित करने के प्रयास किए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) में केवल अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को ही छूट दी, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म से अलग होने के लिए विभिन्न संप्रदायों में प्रोत्साहन हो गया। यूपीए सरकार ने मुस्लिमों के लिए सच्चर कमेटी भी गठित की और कई सारे बदलाव करने की कोशिश की जिन्हें असंवैधानिक माना जाता था। कांग्रेस सरकार द्वारा 'भगवा आतंकवाद' की मनगढ़ंत कहानी भी तैयार की गई, ताकि मुस्लिम वोट उसे मिलें।

मोदी सरकार का मानना है कि उत्तरदायित्व और सुशासन ही चुनावी सफलता सुनिश्चित करता है। सरकार की झूठी आलोचना पर ध्यान दिए बगैर, जनादेश का सम्मान करते हुए अपना काम करते रहना हमारा लक्ष्य है। पिछली सरकारों के विपरीत, मोदी सरकार का मानना है कि अच्छी आर्थिक नीति ही अच्छी राजनीति है। सरकार ने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उच्च मानक तय किए और अपने मूल्यांकन आधार भी तैयार किए है और वह इस परीक्षा के लिए वह सदा तैयार हैं। 2014 से अब तक के राज्य चुनावों में बीजेपी की सफलता इसकी गवाही देती है कि मोदी सरकार केंद्र में अपने काम के और श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में मजबूत संगठन के कारण राजनीतिक सफलताएं प्राप्त करती आ रही है। ■

लेखक भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता (आर्थिक मामले) हैं

पिछले चार वर्षों में अभूतपूर्व महिला सशक्तिकरण

डॉ. सुधा मलैया

नरेंद्र मोदी ने 2014 से 2018 तक चार वर्षों में भारतीय राजनीति का मौसम ऐसा बदला कि मौसम विभाग के सारे आंकड़े भविष्यवाणियां गलत सिद्ध हो गईं। सारे अनुमान धरे रह गए और कयास बेमानी। देश का राजनीतिक मौसम ऐसा बदला कि सारे राज्यों में बदली–बदली सी सरकार नजर आती है। केंद्र से जो अश्वमेध घोड़ा दौड़ा तो प्रत्येक राज्य में साठ वर्षों से आतताई बनकर बैठी कांग्रेस सरकारों का सफाया करता चला गया और 2009 में कांग्रेस मुक्त भारत का मोदी जी का सपना साकार होता चला गया। यह संकल्प छोटा नहीं था। प्राचीन चक्रवर्ती सम्राट के समान मध्य प्रदेश, उत्तरापथ, उत्तर–पूर्व व पश्चिम में विजय पताका फहराता हुआ बढ़ता रहा है यह अद्भुत अश्वरोही Modi=Making of Developed India की ओर।

विश्व में भारत को सशक्त व स्वाभिमानी बनाने के लिए आवश्यक है कौशलयुक्त भारत, डिजिटलाईज्ड भारत और आत्मनिर्भर व स्वावलंबी भारत। जो होगा, एक ओर देश की तरुणाई को कुशल व स्वावलंबी बनाने से और दूसरी ओर महिला शक्ति को सशक्त करने से। मोदी सरकार के असरकारी 4 सालों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महती कार्य हुआ है।

जीवन भर चूल्हे में लकड़ी झोंकते हुए धुंए से माता की आंखों से बहते पानी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री पुत्र ने एक मई 2016 में प्रारम्भ उज्ज्वला योजना द्वारा मात्र दो वर्षों में 3.8 करोड़ महिलाओं को एल.पी.जी. कनेक्शन देकर उनके गहरे अंधेरे में गुम हो गई जीवन की डगर की चांदनी को उजालों से भरा है। जिससे कि देश की माताओं की नज़र की चांदनी न मैली हो और न धुंधली पड़े। हानिकारक ईधन की खपत को समाप्त करते हुए, उज्ज्वला योजना का लक्ष्य 8 करोड़ किया और किया कांग्रेसी सरकारों की देन कोटा राज को समाप्त।

देश की कोई बेटी जन्म से पहले या बाद में असमय मृत्यु को प्राप्त न हो, अभावों में पलती शिक्षा से वंचित न रह जाये, लड़की होने के कारण प्रतिबंधित न हो इसलिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 104 चिन्हित जिलों में बेटियों का जन्म लेना सुरक्षित करके बेटियों का अनुपात भी सुधारा। बेटियां बोझ न हो उनकी शिक्षा भी बेटों की शिक्षा के समान महत्वपूर्ण बनाने के लिए अनेक छात्रवृत्तियों की व्यवस्था से माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ी है।

मातृत्व सुख अनुभव कराने और निश्चिंत करने के लिए मातृत्व लाभ (संशोधित) अधिनियम 2017 के अन्तर्गत मातृत्व अवकाश 3 से 6 महीने करके विश्व में कीर्तिमान रचा गया। अब किसी महिला को पर्ल्सबक (Pearls Buck) के गुड अर्थ (Good Earth) की नायिका के समान बच्चे को जन्म देते ही हाथों में कुदाल या कुदाली नहीं लेनी होगी। बच्चा कुपोषित न रहे इसका ध्यान रखते हुए बहु मॉडल हस्तक्षेप अर्थात् प्रौद्योगिकी के प्रयोग तथा अनेक मंत्रालयों के सम्मिलित प्रयासों से किया जा रहा है।

गर्भवती महिला मां बनने का आनंद महसूस सके और भावी संतान को पालने के इंद्रधनुषी सपने संजो सके, इसलिए 'मिशन इंद्रधनुष' के तहत 80 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित किया और गर्भवती अथवा नवप्रसूता दुग्धपान कराने वाली माताओं को छः हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रधान की जिससे सुरक्षित रहे जच्चा भी और बच्चा भी। 50 लाख से अधिक माताएं इसका लाभ ले सकेंगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना में शिशु की मां और शिशु दोनों स्वस्थ रहें इसलिए 271.66 करोड़ रुपये का भुगतान करके, 1.16 करोड़ गर्भवती महिलाओं की, प्रसव पूर्व 12900 से अधिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर समय पर जांच की और छः लाख से अधिक हाई रिस्क गर्भधारण से पीड़ित महिलाओं की पहचान करके उनके सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था की गई।

केवल इतना ही नहीं उन्हें मातृत्व सुख अनुभव कराने और निश्चिंत करने के लिए मातृत्व लाभ (संशोधित) अधिनियम 2017 के अन्तर्गत मातृत्व अवकाश 3 से 6 महीने करके विश्व में कीर्तिमान रचा गया। अब किसी महिला को पर्ल्सबक (Pearls Buck) के गुड अर्थ (Good Earth) की नायिका के समान बच्चे को जन्म देते ही हाथों में कुदाल या कुदाली नहीं लेनी होगी। बच्चा कुपोषित न रहे इसका ध्यान रखते हुए बहु मॉडल हस्तक्षेप अर्थात् प्रौद्योगिकी के प्रयोग तथा अनेक मंत्रालयों के सम्मिलित प्रयासों से किया जा रहा है।

'कब उसका हर दिल अजीज शौहर उससे किसी भी बात पर नाराज होकर या किसी और नाजनीन से दिल लगा कर उसे अपनी जिन्दगी से तीन तलाक कह कर रफा–दफा कर देगा,' की आशंका में जीती मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनने की दिशा में तीन तलाक के खिलाफ विधेयक लोकसभा में पारित किया। देश की सभी महिलाओं को बराबरी से सम्मानपूर्वक जीने का हक मिले, इस दृष्टि से मुस्लिम महिलाओं को बिना पुरुष अभिभावक के हज पर जाने की प्रक्रिया सरल करके, एकल मां के लिए पासपोर्ट नियम आसान बनाकर तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को प्राथमिकता देकर सामाजिक सशक्तिकरण के ठोस कदम उठाए गए हैं।

स्त्री अपने होने के गर्व को महसूस करे या स्त्री होने के कारण कभी भी कहीं भी दुष्कर्म हो जाने की आशंका में जीने वाली महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने और बलात्कारी, दुष्कर्म करने से डरे, इस हेतु बलात्कारी की सजा पर सरकार अध्यादेश लाई। जिसमें 12 साल से कम उम्र की बालिका से बलात्कार के दोषी को मौत की सजा और 16 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार के दोषी को 10 साल से बढ़ा कर 20 साल की सजा की गई।

केवल यही नहीं नारी शक्ति का भविष्य भी सुरक्षित हो इसलिए 'प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना' के तहत 1.26 करोड़ से अधिक खाते खोले गए जिसमें लगभग 20 हजार करोड़ रुपये जमा किए गए। महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित करने और खुले में शौच को रोकने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पूरे देश में 7.25 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण करके 36 लाख से अधिक गावों और 17 से अधिक राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया।

नारी शक्ति के कौशल युक्त हुए बगैर कुशल भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए कौशल युक्त मुद्रा योजना तथा स्टैंडअप योजना के अंतर्गत महिला/एस.सी./एस.टी/ओ.बी.सी/ उद्यमियों को एक करोड़ रुपये तक के गारंटी मुक्त ऋण देकर नौ करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचाया।

इन सब योजनाओं से महिलाओं का न केवल उनका आत्मविश्वास जगा, बल्कि वे आत्मनिर्भर भी हुईं। देश की वायु सेना के लड़ाकू बेड़े में फाइटर पॉयलट के रूप में तीन महिलाओं–अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह की नियुक्ति ने पूरे देश को गर्व से भर दिया। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार देश की उत्तर–पूर्व में नेपाल, म्यांमार, भूटान सीमा पर तैनात 106 महिला कमांडो ने 26 बाईक पर हैरतअंगेज करतब दिखाकर सबको हैरान किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी तमाम योजनाएं बनाई हैं, जिनसे देश की महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर और सुरक्षित महसूस कर रही है। वे महिलाओं को यह यकीन दिलाने में भी सफल रहे हैं कि उनके सम्मान और विकास के बारे में सोचने और कुछ कर गुजरने वाला आज सरकारी तंत्र के उच्च शिखर पर बैठा है जो नारी शक्ति के साथ खड़ा है। ■

(लेखिका भाजपा प्रकाशन एवं पत्रिका विभाग की सदस्या हैं)

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

.... पिन : ....

दूरभाष : .... मोबाइल : (1)...................................... (2)......................................

ईमेल : ....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :...................................... दिनांक :.............................. बैंक : ....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

सिंगापुर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री ली सीन लूंग से मिलते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

सिंगापुर के क्लिफोर्ड पियर में महात्मा गांधी की अस्थियों के विसर्जित स्थल पर महात्मा गांधी पट्टिका का अनावरण करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

जकार्ता (इंडोनेशिया) में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री जोको विदोदो से हाथ मिलाते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

जकार्ता (इंडोनेशिया) आगमन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते श्री जोको विदोदो के साथ हजारों बच्चे

क्वालालम्पुर (मलेशिया) में मलेशिया के प्रधानमंत्री श्री महातिर मोहम्मद से मिलते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

दिल्ली में दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे के पहले चरण के शुभारम्भ के अवसर पर रोड शो करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20

युवा ऊर्जा से बदलता देश

स्कूली शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार और इनोवेशन पर जोर।

7 आईआईटी, 7 आईआईएम, 14 आईआईआईटी और कई नए विश्वविद्यालयों के साथ उच्च शिक्षा में नए अवसर।

स्किल इंडिया के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण।

पब्लिक, प्राइवेट और पर्सनल सेक्टर में विभिन्न तरीकों से युवाओं को आगे बढ़ने के मजबूत अवसर।

खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत, जहां प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये की सहायता।

बदलता जीवन संवरता कल

जन-धन योजना के जरिए बैंकिंग सुविधा से वंचित गरीबों की बैंकिंग जरूरतें और 'जन सुरक्षा' के माध्यम से गरीब को बीमा मिला।

उज्ज्वला योजना से 3.8 करोड़ गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिए गए। लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन में 7.25 करोड़ से भी अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया।

1 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर।

देश के किसी भी गाँव में अब अँधेरा नहीं है, सौभाग्य योजना के जरिए 4 करोड़ घरों में बिजली पहुँचाई जा रही है।

तेज हुई तरक्की की रफ़्तार

पिछले 4 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक गरीबों को मिले घर।

पिछले 4 वर्षों में 1.69 लाख किमी से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण

2017-18 में 134 किमी प्रतिदिन सड़क का निर्माण किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति पिछली सरकार के 12 किमी प्रतिदिन की तुलना में बढ़कर 27 किमी प्रतिदिन हुई।

2017-18 रहा रेल सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा साल। पिछले 4 वर्षों में 5,469 मानवरहित रेलवे क्रासिंग को समाप्त किया गया।

भारत में पहली बार एसी ट्रेनों की तुलना में हवाई जहाज से सफर करने वालों की संख्या बढ़ी।

पिछड़े वर्गों की अपनी सरकार

अनुसूचित जाति-जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए 95,000 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट।

शिक्षा के माध्यम से समाज का सशक्तिकरण पिछड़ी जाती के छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं द्वारा प्रोत्साहन।

एससी/एसटी एट्रोसिटी एक्ट को और मजबूत बनाया गया।

मुद्रा के अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक लोन पिछड़े वर्गों को।

बाबा साहेब के जीवन से जुड़े पंचतीर्थ के विकास से युवा पीढ़ी को उनसे जोड़ने का प्रयास।

किसान की संपन्नता हमारी प्राथमिकता

किसान की आय दोगुनी करने के लिए बहुआयामी प्रयास

किसान को उसकी लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य

12.5 करोड़ से अधिक किसानों को मिले सॉयल हेल्थ कार्ड

ई-नाम के द्वारा किसानों को मिल रहा फसल का बेहतर दाम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को फसल का कम दाम में बेहतर सुरक्षा कवच

तेज़ गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था

भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली विशाल अर्थव्यवस्था।

FDI में भारी वृद्धि, 36.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 60 बिलियन डॉलर

विश्व भर की रेटिंग एजेंसियों द्वारा भारत को लगातार अच्छी रेटिंग

जीएसटी से कारोबार हो रहा आसान।

बैंकिंग सुधारों से अर्थव्यवस्था को मिल रहा बल।

भ्रष्टाचार पर लगाम पारदर्शी हर काम

नोटबंदी से अब तक सबसे ज्यादा काले धन का पर्दाफाश।

मॉरिशस, सायप्रस, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर से काले धन की रोकथाम के लिए संधियां।

आर्थिक भगोड़ों की सम्पत्तियाँ जब्त की जा रही हैं और भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक पेश किया गया।

बेनामी संपत्ती एक्ट से काले धन के कारोबार पर लगाम।

PMLA एक्ट में बदलाव द्वारा विदेशों में जमा काले धन के बराबर संपत्ती जब्त करना हुआ मुमकिन।

अच्छा स्वास्थ्य अब सबका अधिकार

आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा पहल, करीब 50 करोड़ लोगों को इससे प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का हेल्थ कवरेज मिलेगा।

मिशन इंद्रधनुष में 3.15 करोड़ बच्चों को टीके और 80.63 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण।

प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्रों में 3,000 से अधिक स्टोरों पर जरूरी दवाएं लगभग 50 प्रतिशत कम दामों पर उपलब्ध।

स्टेंट और घुटनों के प्रत्यारोपण की कीमतों में 50 से 70 प्रतिशत की कमी।

विकास की नई गति, नए आयाम

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों में करीब 1 करोड़ मकानों का निर्माण।

100 शहरी केन्द्रों का स्मार्ट सिटी के रूप में चयन और विभिन्न योजनाओं पर 2,01,979 करोड़ रुपये खर्च।

भारतमाला परियोजना के अंतर्गत देश में सड़कों के बहुत बड़े जाल का लक्ष्य, 5,35,000 करोड़ रुपये का नया कार्यक्रम और राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करने का लक्ष्य।

चारधाम महामार्ग, 12,000 करोड़ की लागत से लगभग 900 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास।

नारी शक्ति देश की तरक्की

माँ और शिशु के स्वास्थ की बेहतर देखभाल के लिए विभिन्न योजनाएं।

प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 1.26 करोड़ बालिकाओं के खाते खोले गए।

3.8 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के द्वारा धुआं मुक्त जीवन मिला, एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य बढ़ाकर 8 करोड़ किया गया।

12 वर्ष से कम उम्र की बेटियों के साथ दुष्कर्म पर मृत्यु दंड का प्रावधान और 16 से 20 वर्ष की बेटियों के साथ दुष्कर्म पर 10-20 साल की सजा का प्रावधान।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 7.25 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। 3.6 लाख से अधिक गाँव और 17 राज्यों को खुले में शौच से मुक्त किया गया।

दुनिया देख रही है एक न्यू इंडिया

इतिहास में पहली बार भारत ने दिलेरी दिखाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया।

भारत बना विकास का वैश्विक केंद्र।

पूरे विश्व ने योग को उत्साह से जीवन में अपनाया।

जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में भारत की मुख्य भूमिका।

इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया।

साफ नीयत सही विकास

देश का बढ़ता जाता विश्वास...

अधिक जानकारी के लिए 48months.mygov.in पर जाएं